www.dainikjayantnews.com
कोटद्वार, शनिवार
28 नवम्बर 2026
वर्ष: 49
अंक: 195 पृष्ठ: 6
मूल्य: 2.00

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नरेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोन: 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

गुजरात से जैश-ए-मोहम्मद का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

एटीएस ने एके-47 और 20 जिंदा कारतूस किए बरामद

वडोदरा एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की तैयारी कर रहा था

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड ने वडोदरा से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े मोहम्मद सहारुल इस्लाम को गिरफ्तार किया है। वह असम का रहने वाला है। एटीएस के मुताबिक, वह वडोदरा एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की तैयारी कर रहा था। उसके मोबाइल से एयरफोर्स स्टेशन की फोटो और वीडियो के साथ जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी सामग्री भी मिली है। उसके पास से एके - 47 जैसी ऑटोमैटिक असॉल्ट राइफल, 2 मैगजीन, 23 जिंदा कारतूस, जैश-ए-मोहम्मद का झंडा, 2 मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई है। जांच के मुताबिक, आरोपी असम से बस और ट्रेन के जरिए गुजरात आया था। वह सार्वजनिक जगहों पर आतंकी हमला करने की फिराक में था। वडोदरा में वह रेलवे स्टेशन के पास रुका हुआ था। एटीएस पिछले 6 महीने से उसकी तलाश कर रही थी। गुजरात एटीएस ने 3 जुलाई को आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 8 आतंकियों को गुजरात और मध्य प्रदेश से पकड़ा था। सभी को अलग अलग जिलों से पकड़ा गया। इनमें से दो की उम्र 18 और 19 साल है। ये सभी गुजरात में छद्मरूका एक एक्टिव नेटवर्क बनाने के लिए काम कर रहे थे, ताकि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया सके। सूचना मिलने के बाद, एटीएस ने 5 अलग-अलग टीमें बनाकर एक बड़ा अभियान चलाया था। एटीएस की टीमों ने गुजरात के कई जिलों में सर्चिंग की।



उत्तराखंड कैबिनेट के 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर

आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,700 बढ़ा, अब मिलेंगे 10 हजार प्रतिमाह

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार, 27 नवंबर 2026 को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,700 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव तथा खनन रॉयल्टी को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से प्रदेश की हजारों आशा कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है। वहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।

आशा कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात, मानदेय बढ़कर हुआ10 हजार

कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,700 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अभी तक आशा कार्यकर्ताओं को 8,300 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता था। अब बढ़ोतरी के बाद उन्हें 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। सरकार के इस फैसले से प्रदेशभर में कार्यरत हजारों आशा कार्यकर्ताओं को आर्थिक लाभ मिलेगा। ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने में आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में मानदेय वृद्धि को उनके लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।



आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की तैयारी

कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया। मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई और मानदेय बढ़ाने के संबंध में निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। इस फैसले से प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी मानदेय में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है।

खनन रॉयल्टी में नहीं होगी बढ़ोतरी

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खनन से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि खनन की बढ़ी हुई दरों पर रॉयल्टी में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सरकार के इस निर्णय को खनन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।

कैबिनेट बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं, कर्मचारियों के हितों और खनन से जुड़े विषयों पर निर्णय लिए गए।

प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच यह कैबिनेट बैठक राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार के पांच साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी होने के साथ ही सरकार और संगठन चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश में सामाजिक कल्याण और जनहित से जुड़े वर्गों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सुप्रीम' आदेश मदुरै दीपथून पर आज जलाओ दीपक

तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार से नाराज सुप्रीम कोर्ट

मंदिर ट्रस्ट निलंबित,सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ होगी तैनात

नई दिल्ली (एजेंसी)। तमिलनाडु के तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दीपथून स्तंभ में कार्तिगई दीपम जलाने का विवाद अब न्यायपालिका और राज्य सरकार के बीच आदेश पालन का बड़ा सवाल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को एक विशेष निर्देश दिया था, लेकिन 24 नवंबर को निर्धारित स्थान पर दीप नहीं जलाया गया। इसके बाद अदालत में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उसके आदेशों को अपनी सुविधा के अनुसार बदलना या उन पर बातचीत करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली शामिल थे। अदालत 27 नवंबर को मदुरै के जिला कलेक्टर और तमिलनाडु के अन्य अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। 20 नवंबर के आदेश में 24 नवंबर को दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने साफ किया कि इस सुनवाई में वह पुराने विवाद के सभी पहलुओं के बजाय अपने आदेश के पालन की जांच करेगी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने पाया कि 20 नवंबर के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गई है। जबकि, मदुरै के जिला कलेक्टर ने मद्रास हाई कोर्ट के सामने यह सुनिश्चित करने का वचन दिया था कि आदेश का पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपरनकुंद्रम स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को निलंबित कर दिया है और दो जजों की एक समिति के जरिए मंदिर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया है।



अधिकारी 'बॉस' को खुश करने में लगे हैं

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने पाया कि 20 नवंबर के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गई है। जबकि, मदुरै के जिला कलेक्टर ने मद्रास हाई कोर्ट के सामने यह सुनिश्चित करने का वचन दिया था कि आदेश का पालन किया जाएगा। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि तमिलनाडु प्रशासन संवैधानिक अराजकता की स्थिति में है। बेंच ने कहा कि वे मदुरै के जिला कलेक्टर के शुरुआती बर्ताव से हैरान हैं। कलेक्टर के पास व्यापक शक्तियां होने के बावजूद, उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन न करने की जिम्मेदारी मंदिर प्रशासन पर मढ़ दी। अधिकारियों द्वारा अपने राजनीतिक वरिष्ठों के इशारे पर काम करने के आरोपों पर, पीठ ने कहा कि दावों की जांच करनी होगी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 28 नवंबर को दीपथून पर धार्मिक दीप जलाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इसके लिए उविपिल्लैयार मंडपम में जल रही लौ का इस्तेमाल किया जाए, यदि वह अभी भी जल रही हो। ऐसा संभव नहीं होने पर दीप जलाने की दूसरी व्यवस्था की जा सकती है। अदालत ने श्रद्धालुओं को दरगाह से सभी तरफ कम से कम 50 मीटर की दूरी रखते हुए दीप जलाने की अनुमति भी दी। यह कार्रवाई कोर्ट के 20 नवंबर के आदेश का पालन न करने की वजह से की गई है। इस आदेश में मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के ऊपर स्थित 'दीपाथून' पत्थर के खंभे पर एक बार दीपाम (धार्मिक दीपक) जलाने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट के निर्देशों के बावजूद, 24 नवंबर को दीपक नहीं जलाया गया।

कार व स्कूटी की भिड़ंत, युवक की मौत, एक घायल

कौड़िया तिराहे पर कार ने स्कूटी को मारी टक्कर



दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद लोग

जयन्त प्रतिनिधि कोटद्वार : परिचित की अंत्येष्टि में शामिल होकर लौट रहे दो युवकों की स्कूटी को कौड़िया तिराहे पर एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का बेस चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। गुरुवार रात लकड़ी पड़ाव निवासी अरमान अपने परिचित पटेल मार्ग निवासी सुल्तान के साथ स्कूटी से बिजनौर जिले के टांडा से लौट रहा था। दोनों वहां एक परिचित की अंत्येष्टि में शामिल होने गए थे। कोटद्वार पहुंचने पर कौड़िया तिराहे के समीप एक कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को राजकीय बेस चिकित्सालय पहुंचाया गया। यहां उपचार के दौरान अरमान ने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों के अनुसार, अरमान के सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिससे काफी रक्तस्राव हुआ। वहीं, सुल्तान के पैर में चोट आई है और उसका उपचार चल रहा है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि दुर्घटना के बाद कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है। समाचार लिखे जाने तक मामले में मृतक के स्वजन की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई थी।

हम हिंदू बनना चाहते हैं हिंदू रिवाजों से हों हमारे अंतिम संस्कार!

ईसाई परिवारों ने केरल हाई कोर्ट से लगाई गुहार,कर दी बड़ी मांग

तिरुअनंतपुरम (एजेंसी)। धर्म चुनना किसी भी व्यक्ति की निजी आस्था और स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है। इसी अधिकार को लेकर केरल के एक ईसाई परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। परिवार के आठ सदस्य ईसाई धर्म छोड़कर अपने पूर्वजों के हिंदू धर्म में वापस लौटना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कोल्लम जिले के



कोट्टारक्करा स्थित श्री महागणपति मंदिर में धार्मिक रस्म कराने की मांग की है। परिवार का कहना है कि मंदिर प्रशासन की ओर से करीब पांच महीने तक कोई फैसला नहीं ले पाया है। अब इस मामले में केरल हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई है।

हिंदू धर्म में आस्था, परिवार के सदस्यों ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका- मामला केरल के कोल्लम जिले के पुनालूर क्षेत्र के एक ईसाई परिवार से जुड़ा है। परिवार के आठ सदस्य चर्च ऑफ साउथ इंडिया से जुड़े हैं। याचिकाकर्ता सूर्यलक्ष्मी एस के अनुसार, उनके पूर्वज हिंदू थे और कुरावा समुदाय से संबंध रखते थे। परिवार ने अपनी इच्छा से दोबारा हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया है। परिवार ने 24 जून 2026 को कोट्टारक्करा श्री महागणपति मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी के सामने आवेदन दिया था। उनकी मांग थी कि मंदिर में मत परिवर्तनम यानी धर्म परिवर्तन की धार्मिक रस्म कराई जाए। लेकिन मंदिर प्रशासन ने फिलहाल इंतजाम नहीं किया है। ऐसे में उन्होंने अदालत से दखल देने की गुहार लगाई।

मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी, 25 साल संख्या नहीं बदलेगी

प्रस्ताव पास,लोकसभा में बढ़ेंगी 50 फीसदी सीटें

30 को लोकसभा,2 दिसंबर को राज्यसभा में बिल आएगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। कैबिनेट ने शुक्रवार को लोकसभा सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में करीब एक घंटे बैठक चली। इसमें परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण के नए बिल को मंजूरी दी गई। लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं। 50 फीसदी बढ़ोतरी के बाद ये 815 हो जाएंगी। यानी 272 सीटें बढ़ेंगी। बढ़ाई गई सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। कुल सीटों की यह संख्या अगले 25 साल तक नहीं बदलेगी। सूत्रों के मुताबिक, नए बिल में कुछ बदलाव किए गए हैं, ताकि परिसीमन के बाद किसी भी राज्य की लोकसभा में सीटों की हिस्सेदारी दूसरे राज्यों के मुकाबले कम न हो। सरकार इसे 30 नवंबर को पेश करेगी।



मोदी कैबिनेट ने दी बिल को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार को डिलिमिटेशन के जरिए महिलाओं के लिए 33 फीसदी रिजर्वेशन लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित कानून में सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में एक समान 50 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रावधान है, जबकि 2051 तक सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखा जाएगा। ये फैसला संसद के स्पेशल सेशन के लिए फिर से शुरू होने से कुछ दिन पहले आया है, क्योंकि सरकार अप्रैल में बिल के हारने के बाद इसे पास करने की एक और कोशिश करने की तैयारी कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी है।

अप्रैल में पेश विधायी पैकेज में ये 3 बिल थे शामिल

संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026-इसका उद्देश्य लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को बढ़ाकर 850 सीटें करना और महिला आरक्षण को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करना है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने के लिए एक परिसीमन आयोग गठित करने का प्रस्ताव है। केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 : इसका उद्देश्य दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर की चुनावी व्यवस्था में जरूरी बदलाव करना है। प्रस्तावित संविधान संशोधन के तहत, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 850 तक हो सकती है, जिसमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य शामिल होंगे। परिसीमन वह प्रक्रिया है जिसके तहत रणनीति बनेगी।

दोहरे नाम वाले मतदाताओं की सॉफ्टवेयर से होगी जांच

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ.बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने शुक्रवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में चल रहे अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जो दोहरे मतदाता होंगे, उनकी जांच आयोग के डीएसई सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दलों को बताया कि एसएसआर के तहत मतदाताओं की किसी भी प्रकार की त्रुटि को ठीक करने के लिए दावे, आपत्तियों को दर्ज करने की अवधि तक निरंतर अभियान चलता रहेगा। उन्होंने दलों से अपील की कि मतदाताओं के नाम आदि में त्रुटियों को ठीक करने के लिए बीएलए के माध्यम से भी फॉर्म-8 भरे जाएं। यह भी अवगत कराया कि प्रदेश में ऐसे मतदाता जिनका नाम दो स्थानों पर दर्ज है, उन्हें डीएसई के माध्यम से चिह्नित कर नियमानुसार जांच कर निस्तारित किया जाएगा।

राजनीति यूपी चुनाव पर खरगे बोले-यहां गठबंधन सरकार को लाओ

इमरान को नसीहत,जोश ठीक,लेकिन काम करना है

लखनऊ (एजेंसी)। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं को गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। कहा कि गठबंधन की सरकार लानी है। मोदी-योगी को हराना है। अंदरूनी झगड़ों से जीत मुश्किल होती है। उन्होंने इमरान मसूद के जोश की तारीफ की, साथ ही गठबंधन धर्म निभाने की सलाह भी दी। कहा- हमारे इमरान मसूद हैं, रोज टीवी पर सुनता हूं, जरा जोश के साथ बात करते हैं। लेकिन हमें बातों से ज्यादा काम भी करना है। इसलिए जितना हम लोग मिलकर काम करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि हमारे अजय राय ने प्रधानमंत्री से टक्कर ली। वह थोड़े से चूक गए, नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं रहते। वह गुजरात जाकर बैठते। खड़गे कांग्रेस के संविधान बचाओ मार्च में शामिल होने लखनऊ पहुंचे थे। प्रशासन ने मार्च की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि, खड़गे के जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। पार्टी कार्यालय से करीब 150 मीटर आगे बढ़ने पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने पहले से ही श्री लेयर बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कई कोशिशों के बाद भी कांग्रेसी आगे नहीं बढ़ सके। उधर, पुलिस ने मार्च में शामिल प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा को गिरफ्तार किया।



कार्यालय से डेढ़ सौ मीटर तक ही आगे बढ़ सके कांग्रेसी

पार्टी कार्यालय से करीब डेढ़ सौ मीटर तक बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे थे। लेकिन थ्री लेयर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने उनको रोक दिया। करीब 40 मिनट तक कांग्रेसियों ने आगे जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया। इसके बाद प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद सहित कई सीनियर नेताओं को हिरासत में ले लिया और सबको इको गार्डन लेकर गई। अजय राय ने कहा- योगी सरकार तानाशाही कर रही। संविधान दिवस के दिन संविधान कुचलने का काम सरकार कर रही। ये लोग संविधान को मानने वाले नहीं है। हमारा एक-एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरा है। हम संविधान बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने ओवैसी और चंद्रशेखर की रैली को भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित बताया। कांग्रेस की रैली में आए सुभाष श्रीवास्तव ने कहा हम लोग कभी अंग्रेजों से नहीं डरे। कांग्रेस डरने वाली नहीं है। अंग्रेजों ने हमारे मार्च को रोका था।

संपादकीय

विकास या परिवर्तन, जनता सुनाएगी फैसला

उत्तराखंड की सियासत में 2027 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन अथवा सत्ता में वापसी की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के राजनीतिक भविष्य, नेतृत्व की स्वीकार्यता और जनता के भरोसे की भी परीक्षा होगा। चुनावी रणभूमि तैयार होने लगी है। राजनीतिक दल अपनी–अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हैं। कहीं सरकार की उपलब्धियों का बखान है तो कहीं विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उत्तराखंड की सत्ता का रास्ता किस पार्टी के लिए खुलेगा और किसे जनता के फैसले के सामने अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी।उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा ने 2022 में लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर सत्ता परिवर्तन की पुरानी परंपरा को तोड़ा था। अब 2027 में उसके सामने इस सफलता को दोहराने की चुनौती होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार विकास, धार्मिक पर्यटन, समान नागरिक संहिता, सड़क कनेक्टिविटी और जनकल्याणकारी योजनाओं को अपनी उपलब्धियों के रूप में जनता के सामने रख सकती है। सत्ता में बने रहने के लिए केवल उपलब्धियों का बखान पर्याप्त नहीं होगा। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के प्रति असंतोष जैसे सवालों का जवाब भी सरकार को देना होगा। भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि संगठन और सरकार के बीच तालमेल किस स्तर पर दिखाई देता है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए 2027 का चुनाव राजनीतिक पुनरुत्थान का बड़ा अवसर हो सकता है। विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए अनेक मुद्दे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन मुद्दों को एक मजबूत राजनीतिक अभियान में बदल पाएगी? प्रदेश कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आपसी खींचतान, नेतृत्व की एकजुटता और संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की होगी। केवल सरकार की आलोचना से सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि कांग्रेस के पास प्रदेश के विकास और समस्याओं के समाधान का स्पष्ट खाका मौजूद है। हमेशा की तरह इस बार भी बेरोजगारी और युवाओं का भविष्य, पहाड़ों से लगातार होता पलायन, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और रोजगार, अंकिता भंडारी प्रकरण और न्याय से जुड़े सवाल, मूल निवास, भू–कानून और स्थानीय पहचान, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, महंगाई तथा आम आदमी की आर्थिक परेशानियां, स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल व्यवस्थाएं आदि मुद्दों पर राजनीतिक दलों की घोषणाओं से अधिक उनकी नीतियों और जमीनी कामकाज की परीक्षा होगी। हर चुनाव के अपने अलग समीकरण होते हैं। इस बार मतदाता केवल पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि स्थानीय उम्मीदवार, क्षेत्रीय विकास और सरकार के कामकाज को भी कसौटी पर रख सकता है। पहाड़ के मतदाता के लिए गांव में अस्पताल, स्कूल, सड़क और रोजगार का सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना मैदानी क्षेत्रों में महंगाई, व्यापार, यातायात और शहरी सुविधाओं का। यही क्षेत्रीय विविधता उत्तराखंड के चुनाव को दिलचस्प बनाती है। उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय मुद्दों का हमेशा महत्व रहा है। ऐसे में छोटे राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए अपनी राजनीतिक निरंतरता साबित करने का अवसर होगा तो कांग्रेस के लिए वापसी की संभावनाओं को जमीन पर उतारने की चुनौती। दोनों दलों को यह समझना होगा कि उत्तराखंड की जनता अब केवल राजनीतिक भाषणों और चुनावी घोषणाओं से संतुष्ट होने वाली नहीं है। उसे अपने जीवन में बदलाव चाहिए। उत्तराखंड की सियासत में 2027 का सबसे बड़ा सवाल यही है–क्या जनता विकास के नाम पर एक बार फिर भरोसा जताएगी या बदलाव की नई इबारत लिखेगी?

संतुलित मस्तिष्क के लिये आवश्यक है आवेगों पर नियन्त्रण



कांतिलाल मांडोत

व्यवस्थित एवं समुन्नत शील जीवन का निर्माण संतुलित मस्तिष्क से ही संभव है। संतुलित मस्तिष्क आवेगों पर नियंन्त्रण कर के प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति स्वभावतः अपराधी नहीं होता किन्तु आवेग उसे अपराध में झोंक देते हैं। आवेग एक मानसिक आंधी है, वह मानव के मस्तिष्क को असंतुलित ही नहीं करती कई बार तो उसे विचार शून्य तक बना देती है। आवेग की आंधी में मस्तिष्क का अस्तित्व ही विलुप्त सा हो जाता है ।अनेक दुष्कर्म व्यक्ति के द्वारा उसी अवस्था में होते है।मस्तिष्क व्यक्ति के जीवन और चरित्र को संतुलित करता है। वही जब असंतुलित हो जाता है तो उस समय मानव क्या कर बैठे कुछ भी नहीं कहा जा सकता।अपने आवेगों को नियन्त्रित करना सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा तप है।आवेगों का जन्म बाह्य परिस्थितियो से जुड़ कर होता है। अतः बहुत उचित होगा कि हम अपने बाह्य वातावरण को इतना सुलझा हुआ रखे कि आवेग पैदा होने जैसा कुछ हो ही नहीं किन्तु इतना सब कुछ कर लेने पर भी इतना तो होगा ही कि सारे व्यक्ति जो अपने से जुड़े है वे अपनी तरह ही सोचेंगे, यह अवश्यक नहीं। अतःपरिस्थितियों में प्रतिकूलता तो बनी ही रहने वाली है। परिस्थिति की प्रतिकूलताओं को सहर्ष स्वीकार कर अपने आवेगों को दबाए रखना और मस्तिष्क के संतुलन को सुरक्षित रखना सच्चा और अच्छा जीवन जीने की कला है। पड़ौसी देश ने युद्ध भारत को महा युद्ध के लिये उकसाने में कोई कमी नहीं रखी किन्तु भारतीय सेना और संचालकों ने आवेगों से बचकर अपने संतुलन को बनाये रखा और देशको व्यापक युद्ध से बचा लिया जिसकी सारे विश्व में प्रशंसा हुई है। शक्ति शाली होकर भी संतुलित रहना एक महान कार्य है। भारत निश्चित ही अपनी महानता के अनुरुप सहनशीलता और विवेक पूर्वक आगे बढ़ा । धैर्य और संतुलन ने उसे सफलता के शिखर पर समारुढ़ कर दिया । आज विश्व में चारों तरफ आवेग पूर्ण वातावरण व्याप्त हो रहा है। व्यक्ति असंतुलित जी रहा है। किसका कब क्या हो जाए और कब कौन क्या कर बैठे, कुछ कहा नहीं जा सकता ।ऐसे विषम वातावरण में धर्म ही है जो समता और संतुलन की दिशा प्रदान करता है। कहने को आज व्यक्ति स्वतन्त्र है, यदि बहुत गहरे अर्थों में देखा जाए तो मानव में स्वतन्त्रता का कहीं कोई अंश आपको नहीं मिलेगा। विचार और व्यवहार दोनों स्तर पर आज भी व्यक्ति बहुत कुछ परतन्त्र है ।जहां तक भाव जगत का प्रश्न है व्यक्ति वहां आवेगों के अधीन चलता है।

बल्ले से निकला वैभव, क्रिकेट के आकाश में नया सूर्य



ललित गर्ग

क्रिकेट के इतिहास में कुछ दिन केवल कैलेंडर की तारीख बनकर नहीं आते, वे इतिहास के पन्नों पर अमिट हस्ताक्षर कर जाते हैं। मंगलवार का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए ऐसा ही एक मंगलमय दिवस बनकर सामने आया, जब महज पंद्रह वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने दोहा में अपने बल्ले से ऐसा सूर्य उदय किया, जिसकी रोशनी ने पूरी क्रिकेट दुनिया को चकाचौंध कर दिया। जिस उम्र में किशोर सपनों की उड़ान भरना शुरू करते हैं, उस उम्र में वैभव ने क्रिकेट के आकाश में अपने नाम का ऐसा ध्वज फहरा दिया, जिसे आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा। वैभव ने केवल 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर दिया। 28 गेंदों में शतक, महज 40 गेंदों में 150 रन और एक पारी में 28 छक्के-ये आंकड़े किसी वीडियो गेम की काल्पनिक स्कोरशीट जैसे लगते हैं, लेकिन वैभव ने इन्हें हकीकत की पिच पर उतार दिया। सूर्यवंशी की इस आतिशी पारी से दुनिया में खलबली मच गयी है, देश और दुनिया में बड़ी-बड़ी खबरों को दबा दिया है इस खबर ने। आज दुनिया के क्रिकेट जगत में सूर्यवंशी के खेल-वैभव की चर्चा हर जबान पर है। क्रिकेट के दिग्गज उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। साथ ही सवाल भी पूछ रहे हैं कि उन्हें टी-20 व वन डे की भारतीय टीम में बतौर ओपनर कब जगह मिल पायेगी? 204 रनों की उनकी तूफानी पारी में 168 रन केवल छक्कों से आए। बल्ले से निकली हर गेंद मानो सीमा रेखा के पार जाकर एक नया इतिहास लिख रही थी। यह केवल रन बनाने की पारी नहीं थी, बल्कि क्रिकेट की सीमाओं को चुनौती देने वाली एक अद्भुत बल्लेबाजी थी।

भारतीय क्रिकेट ने समय-समय पर ऐसी प्रतिभाओं को जन्म दिया है, जिन्होंने दुनिया को भारतीय क्रिकेट का लोहा मनवाया। सुनील गावस्कर की तकनीक, कपिल देव का साहस, सचिन तेंदुलकर की विलक्षणता, सौरव गांगुली का आत्मविश्वास, महेंद्र सिंह धोनी की निर्णायक क्षमता और विराट कोहली की आक्रामक निरंतरता-इन सबने भारतीय क्रिकेट को गौरव दिया। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की कहानी इसलिए अलग है क्योंकि यह कहानी अभी किशोरावस्था में ही असाधारण उपलब्धियों का शंखनाद कर रही है। वैभव का बल्ला इस समय केवल गेंद को नहीं पीट रहा, बल्कि क्रिकेट की पुरानी धारणाओं को भी चुनौती दे रहा है और अपने कीर्तिमान से नया इतिहास बना रहा है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास है, निर्भीकता है, आक्रामकता है और सबसे बढ़कर एक स्वाभाविक लय है। वे गेंदबाज के नाम, प्रतिष्ठा या अनुभव से भयभीत होते दिखाई नहीं देते। उनकी बल्लेबाजी देखकर लगता है कि गेंद उनके लिए चुनौती नहीं, अवसर है और सीमा रेखा उनके लिए कोई दीवार नहीं, बल्कि एक आमंत्रण है।

वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धियों की फेहरिस्त भी कम चमत्कारी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में दस मैचों में 185 के स्ट्राइक रेट से 295 रन और आईपीएल की 23 पारियों में 228 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से 1028 रन उनकी असाधारण क्षमता का प्रमाण हैं। आईपीएल के 2026 सत्र में 72 छक्के लगाकर उन्होंने एक सीजन में सर्वाधिक छक्कों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा और ऑरेंज कैप हासिल की। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां निश्चित रूप से सामान्य प्रतिभा की निशानी नहीं हैं। दोहा की इस पारी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि वैभव को भारतीय वनडे और टी-20 टीम में अवसर कब मिलेगा। यह स्वाभाविक मांग है कि ऐसी विलक्षण प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर आजमाया जाए, लेकिन इसके साथ धैर्य और विवेक भी जरूरी है। प्रतिभा को अवसर चाहिए, पर अवसर के साथ संरक्षण, मार्गदर्शन और मानसिक तैयारी भी उतनी ही आवश्यक है। क्रिकेट केवल बल्ले की ताकत का खेल नहीं, बल्कि परिस्थितियों, दबाव, रणनीति और मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा है।

सोलह वर्ष की उम्र में सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तान के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उतारने का उदाहरण आज भी प्रेरणा देता है। सचिन ने उस अवसर को इतिहास में बदल दिया। वैभव के सामने भी संभावनाओं का विराट आकाश है। उन्हें अवसर अवश्य मिलने चाहिए, लेकिन उनके क्रिकेटीय विकास की गति और दिशा को समझते हुए। भारतीय क्रिकेट प्रशासन के लिए यह एक ऐसी प्रतिभा है, जिसे जल्दबाजी में दबाव के हवाले करने के बजाय सही ढंग से तराशने की जरूरत है। आज दुनिया के गेंदबाज भी वैभव की बल्लेबाजी को ध्यान से पढ़ रहे होंगे। उनकी कमजोरियां तलाशने, उनकी हिटिंग पावर को रोकने और उनके आक्रामक तेवरों पर अंकुश लगाने की रणनीतियां बन रही होंगी। यही चुनौती वैभव के लिए अगला पड़ाव है। उन्हें अपनी तकनीक में विविधता, शॉट चयन में परिपक्वता और परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करने की क्षमता विकसित करनी होगी। क्योंकि क्रिकेट में असली महानता केवल रिकॉर्ड बनाने में नहीं, बल्कि रिकॉर्ड बनने के बाद भी निरंतर ऊंचाई पर टिके रहने में है। साथ ही कुछ लोगों का मानना है कि मौलिक व आक्रामक खेल वाले खिलाड़ी विरले ही पैदा होते हैं, लेकिन समय पर बड़े अवसर न मिलने का नकारात्मक प्रभाव उनके खेल में पड़ सकता है। साथ ही जरूरी है कि वैभव अपने आक्रामक खेल को बनाये रखें, उसमें निरंतरता रहे और वे क्रिकेट की आधुनिक तकनीकों से रूबरू होते रहें। हर दिन वे अपने खेल के लिये जागरूक रहे एवं आने वाली चुनौतियां के लिये स्वयं को सक्षम बनाये। निश्चित रूप से अधिक इंटरनेशनल मैच खेलना, उनके खेल में निखार लाएगा। जाहिर है उनकी हालिया आतिशी पारी के बाद दुनिया के तमाम गेंदबाज उन पर हावी होने के रास्ते तलाश रहे होंगे। वे उनकी असाधारण प्रतिभा को काबू करने के नुस्खे तलाश रहे होंगे। उनकी हिटिंग पावर को रोकने की व्यूह रचना की जा रही होगी। फिर भी मंगलवार की वह पारी अपने आप में एक युगांतकारी चमत्कृत करने वाली घटना है। जिस उम्र में अधिकांश खिलाड़ी बड़े मंच का सपना देखते हैं, उस उम्र में वैभव ने मंच को ही अपने नाम कर लिया। उनके बल्ले से निकले छक्के केवल गेंदों को सीमा के पार नहीं ले गए, उन्होंने भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी के सपनों को भी आसमान दे दिया। सूर्यवंशी का यह सूर्य अभी अस्त होने के लिए नहीं, निरंतर उदित होने के लिए आया है। उनके बल्ले से निकलती रनों की रोशनी भारतीय क्रिकेट के भविष्य को आलोकित करने की क्षमता रखती है। निस्संदेह, यह केवल एक रिकॉर्ड नहीं, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में लिखा गया एक स्वर्णिम पृष्ठ है। आज पूरे क्रिकेट जगत को इस किशोर प्रतिभा को सलाम करना चाहिए और कहना चाहिए-वैभव, तुम्हारे बल्ले का यह सूर्य जितना चमक रहा है, उतनी ही उज्ज्वल तुम्हारी क्रिकेट यात्रा की संभावनाएं हैं। आने वाला समय तय करेगा कि यह पारी केवल एक रिकॉर्ड बनकर रह जाती है या एक ऐसे स्वर्णिम क्रिकेट-ग्रंथ की पहली पंक्ति बनती है, जिसकी गाथा आने वाली पीढ़ियां गर्व से पढ़ेंगी।

भोजन पैकेट पर चेतावनी : स्वास्थ्य अधिकार की बड़ी जीत



कुमार कृष्णन

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य को बाजार के व्यावसायिक हितों से ऊपर रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चेतावनी लेबल किसी उत्पाद पर प्रतिबंध नहीं है और न ही उपभोक्ता की पसंद पर नियंत्रण। यह उसे सही जानकारी देकर स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाने का माध्यम है। अब असली परीक्षा केंद्र सरकार और एफएसएसएआई की है। क्या वे समयबद्ध तरीके से वैज्ञानिक और प्रभावी नियम लागू कर पाएंगे? क्या खाद्य कंपनियों को बिना किसी भेदभाव के उनका पालन करना होगा? क्या बच्चों को स्वस्थ खानपान की व्यावहारिक शिक्षा मिलेगी?



क्या किसी खाद्य पदार्थ का आकर्षक पैकेट उसकी गुणवत्ता और स्वास्थ्य के लिए उपयोगिता की गारंटी हो सकता है? क्या चमकदार विज्ञापनों, लुभावने दावों और स्वाद के पीछे छिपी चीनी, नमक तथा वसा की अधिक मात्रा के बारे में उपभोक्ता को पर्याप्त जानकारी मिलती है? बाजार में उपलब्ध पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की दुनिया में ये सवाल अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। भारत में खानपान की बदलती आदतों, तेजी से बढ़ते प्रसंस्कृत खाद्य बाजार और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बीच सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है।

26 नवंबर 2026 को संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर सामने की ओर स्पष्ट चेतावनी लेबल लगाने की व्यवस्था प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि जिन खाद्य पदार्थों में चीनी, नमक या वसा की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होगी, उनके पैकेट पर अलग-अलग षट्कोणीय चेतावनी चिह्न लगाने होंगे। प्रत्येक चिह्न में संबंधित पोषक तत्व का चित्र और 'हाई शुगर', 'हाई साल्ट' या 'हाई फैट' लिखा होना चाहिए। यदि किसी उत्पाद में एक से अधिक तत्वों की मात्रा अधिक है, तो प्रत्येक के लिए अलग चेतावनी देनी होगी। एक ही चिह्न में सभी चेतावनियों को समेट देना पर्याप्त नहीं होगा।

इस फैसले का महत्व केवल खाद्य पदार्थों के पैकेट पर कुछ शब्द छापने तक सीमित नहीं है। यह उपभोक्ता के जानने के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार और खाद्य कंपनियों की जवाबदेही से जुड़ा प्रश्न है। बाजार में खरीदारी करते समय उपभोक्ता को यह जानने का अवसर मिलना चाहिए कि वह जिस खाद्य पदार्थ को खरीद रहा है, उसमें स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक तत्व कितनी मात्रा में मौजूद हैं। यह जानकारी किसी कानूनी औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि आसानी से समझ में आने वाली भाषा और संकेतों में उपलब्ध होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश '3एस एंड अवर हेल्थ सोसायटी' की ओर से दायर जनहित याचिका पर आया है। इस संगठन ने पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर सामने की ओर पोषण संबंधी चेतावनी लगाने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने एफएसएसएआई की प्रस्तावित व्यवस्था में कई कमियां रेखांकित की थीं। प्राधिकरण ने पहले सुझाव दिया था कि शुरुआती चरण में उन उत्पादों पर चेतावनी लगाई जाए जिनमें दो या अधिक चिंताजनक पोषक तत्व निर्धारित सीमा से ज्यादा हों। बाद में इस व्यवस्था का विस्तार करके किसी एक तत्व की अधिकता वाले उत्पादों को भी इसमें शामिल किया जाए। अदालत ने इस दो चरणों वाली व्यवस्था पर सवाल उठाया।

अदालत का तर्क था कि यदि किसी उत्पाद में चीनी की मात्रा अपने आप में अधिक है, तो उसे चेतावनी के दायरे में लाने के लिए नमक या वसा की अधिकता की प्रतीक्षा क्यों की जाए? नमक की अधिकता भी स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है और संतृप्त वसा की अधिकता भी। किसी एक तत्व की अधिकता को नजरअंदाज करना उपभोक्ता के हितों के विरुद्ध होगा। इसीलिए अदालत ने एकल चरण वाली व्यवस्था पर जोर दिया, जिसके तहत किसी एक चिंताजनक तत्व की निर्धारित सीमा पार होने पर भी संबंधित चेतावनी लगानी होगी।

फैसले का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि चीनी और वसा की मात्रा तय करने के लिए केवल बाहर से मिलाई गई चीनी या वसा को आधार नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एफएसएसएआई को निर्देश दिया कि चेतावनी के लिए चीनी के मामले में कुल शर्करा और वसा के मामले में संतृप्त वसा को ध्यान में रखा जाए। नमक भी चिंताजनक पोषक तत्वों में शामिल रहेगा। इसका अर्थ है कि किसी खाद्य पदार्थ में मौजूद कुल शर्करा और संतृप्त वसा की वास्तविक मात्रा के आधार पर वैज्ञानिक मानक तैयार किए जाएं। केवल यह बताना पर्याप्त नहीं होगा कि निर्माण के दौरान कितनी अतिरिक्त चीनी या वसा मिलाई गई है।

अदालत ने एफएसएसएआई को इन पोषक तत्वों की निर्धारित सीमाओं पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। सीमाएं इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि लगभग हर उत्पाद पर चेतावनी लगने लगे और इतनी अधिक भी नहीं कि वास्तव में जोखिम वाले उत्पाद इसके दायरे से बाहर रह जाएं। यदि हर पैकेट पर चेतावनी होगी तो उपभोक्ता धीरे-धीरे उसके प्रति संवेदनहीन हो सकता है। दूसरी ओर, सीमा बहुत ऊंची रखने से चेतावनी व्यवस्था का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक साक्ष्यों और भारतीय आबादी की पोषण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर संतुलित मानक तय करना जरूरी है।

इस निर्णय के पीछे सार्वजनिक स्वास्थ्य की गंभीर चिंता है। भारत में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और हृदय संबंधी बीमारियां बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। खानपान में अत्यधिक चीनी, नमक और संतृप्त वसा की मौजूदगी इन समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकती है। विशेष रूप से बच्चों और किशोरों की खाद्य आदतें चिंता का विषय हैं। बाजार में रंगीन पैकेटों में मिलने वाले चिप्स, बिस्कुट, मीठे पेय, चॉकलेट और तैयार नाश्ते बच्चों को आकर्षित करते हैं। विज्ञापन भी उनकी पसंद को प्रभावित करते हैं। कई बार माता-पिता उत्पाद के आकर्षक नाम और पैकेट पर लिखे स्वास्थ्य संबंधी दावों से प्रभावित होकर उन्हें बेहतर विकल्प समझ लेते हैं।

यहीं चेतावनी लेबल की उपयोगिता सामने आती है। पैकेट के पीछे छपी पोषण संबंधी तालिका में ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चीनी और वसा की जानकारी होती है, लेकिन सामान्य उपभोक्ता के लिए उसका अर्थ समझना आसान नहीं होता। खरीदारी के समय हर व्यक्ति के पास आंकड़ों का विश्लेषण करने का समय और तकनीकी ज्ञान भी नहीं होता। सामने की ओर स्पष्ट चेतावनी इस कठिनाई को कम कर सकती है। लाल षट्कोणीय चिह्न और उसके साथ संबंधित चित्र तथा शब्द उपभोक्ता को तुरंत सावधान कर सकते हैं। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो पोषण संबंधी जानकारी पढ़ने या समझने में कठिनाई महसूस करते हैं।

भारत जैसे भाषाई और सामाजिक विविधता वाले देश में चित्रात्मक चेतावनियों का महत्व और बढ़ जाता है। केवल अंग्रेजी में लिखी जानकारी हर उपभोक्ता तक समान रूप से नहीं पहुंच सकती। चित्र और सरल शब्द मिलकर व्यापक आबादी तक संदेश पहुंचा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक चेतावनी चिह्न को अलग रखने और उसे स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकने योग्य बनाने पर जोर दिया है। अदालत के निर्देश के अनुसार प्रत्येक षट्कोणीय चिह्न पैकेट के मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र का लगभग चार से पांच प्रतिशत स्थान घेरेगा। अक्षरों का आकार भी ऐसा होना चाहिए कि सामान्य परिस्थितियों में खरीदारी के समय चेतावनी आसानी से पढ़ी जा सके।

इस फैसले का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष खाद्य उद्योग की जवाबदेही है। लंबे समय से खाद्य कंपनियां अपने उत्पादों को स्वाद, सुविधा और आकर्षक पैकेजिंग के आधार पर बेचती रही हैं। विज्ञापनों में कई बार उत्पादों को ऊर्जा, सक्रियता और खुशहाली से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन उपभोक्ता को उत्पाद की वास्तविक पोषण स्थिति बताने की जिम्मेदारी भी कंपनियों की है। किसी खाद्य पदार्थ को बाजार में बेचने की अनुमति मिल जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसका नियमित और अधिक मात्रा में सेवन स्वास्थ्य के लिए उचित है।

वैश्विक स्तर पर भी इस विषय पर बहस होती रही है। चिली और मेक्सिको जैसे देशों ने अधिक चीनी, नमक और वसा वाले खाद्य पदार्थों की पहचान आसान बनाने के लिए सामने की ओर चेतावनी लेबल की व्यवस्था अपनाई है। भारत में भी इस दिशा में लंबे समय से मांग उठती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दोहरे मानदंडों पर भी चिंता जताई। यदि कंपनियां दूसरे देशों में उपभोक्ताओं को स्पष्ट चेतावनी देने वाली व्यवस्था स्वीकार करती हैं, तो भारत में वैसी ही व्यवस्था का विरोध क्यों होना चाहिए? भारतीय उपभोक्ताओं को भी उतनी ही सुरक्षा और जानकारी मिलनी चाहिए जितनी दूसरे देशों के नागरिकों को मिलती है।

हालांकि, केवल चेतावनी चिह्न लगा देना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए एफएसएसएआई को पोषक तत्वों की सीमा, चिह्नों के आकार, रंग, स्थान और अक्षरों की स्पष्टता के संबंध में वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक मानक तय करने होंगे। कंपनियों को नियमों का पालन करने के लिए समय देना आवश्यक हो सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक नहीं खिंचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के लिए लगभग चार महीने की समयसीमा स्वीकार की है। नियमों की अधिसूचना के बाद खाद्य कारोबार से जुड़ी कंपनियों को अनुपालन के लिए एक वर्ष का संक्रमणकालीन समय देने के प्रस्ताव पर भी विचार हुआ है। अदालत ने मामले को दस सप्ताह बाद फिर सूचीबद्ध करने और प्रगति की जानकारी देने को कहा है।

एक अन्य चिंता यह है कि यदि कंपनियां चीनी, नमक और वसा की मात्रा कम करने के लिए उनके स्थान पर कृत्रिम मिठास, परिरक्षक और अन्य रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक इस्तेमाल करने लगें तो समस्या का नया रूप सामने आ सकता है। इसलिए नियमन केवल तीन पोषक तत्वों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले विकल्पों और अतिरिक्त रासायनिक पदार्थों की सुरक्षा पर भी निगरानी जरूरी है। कंपनियों को केवल चेतावनी से बचने के लिए एक जोखिमपूर्ण तत्व की जगह दूसरा संदिग्ध तत्व इस्तेमाल करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों में पोषण संबंधी साक्षरता बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया है। स्कूलों के पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलाव करने के साथ कार्यशालाओं, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों और व्यावहारिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ खानपान की समझ देने की जरूरत बताई गई है। यह पहल दूरगामी महत्व रखती है। बच्चों को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं है कि कौन-सा भोजन अच्छा है और कौन-सा खराब। उन्हें यह भी सिखाना होगा कि पैकेट पर लिखी जानकारी कैसे पढ़ें, पोषण संबंधी दावों का अर्थ कैसे समझें और विज्ञापन तथा वास्तविक खाद्य गुणवत्ता में अंतर कैसे पहचानें।

खाद्य सुरक्षा का सवाल केवल शहरी मध्यमवर्ग तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों और निम्न आय वाले परिवारों में भी पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की पहुंच बढ़ रही है। कम कीमत और आसानी से उपलब्ध होने के कारण इनका इस्तेमाल बढ़ा है। दूसरी ओर, हर व्यक्ति के पास पौष्टिक भोजन खरीदने की समान आर्थिक क्षमता नहीं है। इसलिए चेतावनी लेबल के साथ सस्ती और पौष्टिक खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन और विद्यालयी पोषण कार्यक्रमों को भी पोषण संबंधी वैज्ञानिक मानकों से जोड़ना होगा।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य को केवल व्यक्ति की निजी जिम्मेदारी मानकर सरकार और बाजार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। स्वस्थ भोजन चुनना उपभोक्ता का अधिकार है, लेकिन सही जानकारी उपलब्ध कराना सरकार और खाद्य उद्योग का दायित्व है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार को व्यापक अर्थ देता है, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। वहीं अनुच्छेद 47 राज्य को पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने की जिम्मेदारी सौंपता है। इसलिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उनके बारे में सही जानकारी सुनिश्चित करना महज प्रशासनिक काम नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व भी है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य को बाजार के व्यावसायिक हितों से ऊपर रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चेतावनी लेबल किसी उत्पाद पर प्रतिबंध नहीं है और न ही उपभोक्ता की पसंद पर नियंत्रण। यह उसे सही जानकारी देकर स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाने का माध्यम है। अब असली परीक्षा केंद्र सरकार और एफएसएसएआई की है। क्या वे समयबद्ध तरीके से वैज्ञानिक और प्रभावी नियम लागू कर पाएंगे? क्या खाद्य कंपनियों को बिना किसी भेदभाव के उनका पालन करना होगा? क्या बच्चों को स्वस्थ खानपान की व्यावहारिक शिक्षा मिलेगी?

खाद्य पदार्थों का बाजार नागरिकों के स्वास्थ्य की कीमत पर मुनाफा कमाने का माध्यम नहीं बन सकता। उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार है कि उसके भोजन में क्या है। स्वस्थ समाज का निर्माण तभी संभव है, जब भोजन केवल स्वाद और व्यापार का विषय न रहकर पोषण, सुरक्षा और नागरिक अधिकार का प्रश्न भी बने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वास्तविक सफलता इसी में होगी कि पैकेट पर चेतावनी के चिह्न दिखाई देने के साथ-साथ देश की खाद्य संस्कृति और बाजार की जवाबदेही में भी बदलाव आए।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

पीआरडी जवानों ने दिया धरना

365 दिन रोजगार और मूल वेतन पर डीए देने की मांग, तहसील परिसर में किया प्रदर्शन


कोटद्वार तहसील परिसर में मांगों को लेकर धरना देते पीआरडी जवान।

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : 365 दिन रोजगार और होमगार्ड की भांति मूल वेतन पर महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) जवानों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। जवानों ने प्रदेश सरकार से मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा। प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के ब्लाक अध्यक्ष दिनेश कुमार और सलाहकार दर्शन सिंह के नेतृत्व में पीआरडी जवान तहसील परिसर में एकत्र हुए। यहां उन्होंने मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर धरना दिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि विभिन्न विभागों में तैनात पीआरडी जवान पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। न्यूनतम मानदेय में परिवार का भरण-पोषण करना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि पीआरडी जवानों को भी वर्षभर रोजगार की गारंटी दी जानी चाहिए। साथ ही होमगार्ड की भांति मूल वेतन पर महंगाई भत्ता दिया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। जवानों ने प्रदेश सरकार से उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगों की अनदेखी होने पर आंदोलन जारी रखा जाएगा। इस मौके पर हरीश चंद्र, सुनील कुमार, पपेंद्र कुमार, कुलदीप कुमार, विजय पंत, विरेंद्र प्रसाद, मनोज भट्ट, राकेश सिंह, रवि कुमार, जितेंद्र गुप्ता, राकेश जुयाल और पंकज कुमार आदि मौजूद रहे।

शाखा डाकघरों को उच्चीकृत करने की उठाई मांग

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : क्षेत्र में बढ़ती आबादी के साथ डाक सेवाओं का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नागरिक मंच ने क्षेत्र के शाखा डाकघरों और उप डाकघरों को उच्चीकृत किए जाने की मांग उठाई है।

मंच का कहना है कि वर्तमान जरूरतों के अनुरूप डाकघरों का विस्तार होने से आमजन को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इस संबंध में मंच के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश नैथानी और सचिव अतुल भट्ट ने डाक अधीक्षक को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि डाक विभाग की ओर से कई वर्ष पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की स्थापना की गई थी। इनमें कोटद्वार क्षेत्र के डाकघर भी शामिल हैं। उस समय की आबादी और जरूरतों के अनुरूप स्थापित किए गए डाकघरों पर अब उपभोक्ताओं का दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए डाकघरों का उच्चीकरण किया जाना जरूरी है। इसके तहत एकल डाकघरों को शाखा डाकघर और शाखा डाकघरों को उप डाकघर के रूप में उच्चीकृत किया जाना चाहिए। इससे डाक सेवाओं का विस्तार होगा और लोगों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर सुविधाएं मिले।

महिलाओं ने विद्यार्थियों को दी स्वेटर


बच्चों को स्वेटर देती महिलाएं

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : क्षेत्र की महिलाओं की ओर से राजकीय इंटर कालेज कोटद्वार के मेधावी विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित की गई। इस दौरान अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी बच्चों की मदद के लिए आगे आने की अपील की गई।

शुक्रवार को इंटर कालेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने साठ बच्चों को स्वेटर वितरित की। साथ ही बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। कहा कि मेहनत करने वाले बच्चों को जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। बच्चों को स्वेटर देने वालों में उमा जैन, सुशीला गर्ग व ममता रही। प्रधानाचार्य मुकेश रावत ने तीनों महिलाओं का आभार व्यक्त किया।

बाल विवाह सामाजिक बुराई, शिक्षा और विकास में बनता है बाधक



जयन्त प्रतिनिधि। सतपुली : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी के दिशा–निर्देशन में राजकीय पॉलिटेक्निक सतपुली में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सिविल जज सतपुली एवं कोटद्वार श्रीमती सोनिया ने छात्राओं को बाल अपराध, बाल विवाह तथा पॉक्सो एक्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर सिविल जज सोनिया ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई होने के साथ ही कानून का उल्लंघन भी है। यह बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बड़ी बाधा बनता है तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकता है। उन्होंने छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया। शिविर के दौरान सभी छात्राओं को बाल विवाह के खिलाफ शपथ भी दिलाई गई। छात्राओं ने संकल्प लिया कि वे अपने परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी भी बालिका का बाल विवाह नहीं होने देंगी। बाल विवाह की जानकारी मिलने पर पंचायत एवं संबंधित सरकारी विभागों को सूचित करेंगी तथा सभी बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हुए बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण में सहयोग करेंगी। इस मौके पर सतपुली थाने में तैनात उपनिरीक्षक दिनेश कुमार ने छात्राओं को महिला सुरक्षा, एमवी एक्ट, यातायात नियमों तथा अन्य कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। शिविर का संचालन पीएलवी सतपुली पुष्पेंद्र राणा ने किया। इस मौके पर प्रभारी प्रधानाचार्य किरन, किरण असवाल, प्रभारी प्रधानाचार्य आकाशदीप कुकरेती, सहायक लेखाकार नितिन चंद्र, पुस्तकालय अध्यक्ष गौरव सेमवाल, व्याख्याता (यांत्रिकी) विनीत त्यागी आदि मौजूद थे।

दो दिवसीय अंतर महाविद्यालयी योग प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ

13 महाविद्यालयों की 18 महिला एवं पुरुष टीमों के प्रतिभागी दिखा रहे हैं योग कौशल



जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार :राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार में श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय (27 एवं 28 नवंबर, 2026) अंतरमहाविद्यालयी महिला एवं पुरुष योग प्रतियोगिता का शुभारंभ आज गरिमामय वातावरण में हुआ।कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डी.एस. नेगी, विशिष्ट अतिथि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के क्रीड़ा सचिव डॉ. पुष्कर गोड तथा राजकीय महाविद्यालय भाबर के प्राचार्य डॉ. हरीश चंद्र द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं मां शारदा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस दो दिवसीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय से संबद्ध 13 महाविद्यालयों की कुल 18 महिला एवं पुरुष टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों में योगासन की विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर योग का प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त कर चुके प्रतिभागी अपनी योग प्रतिभा, शारीरिक संतुलन, लचीलापन, एकाग्रता तथा विभिन्न योगासनों में दक्षता का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता के प्रथम दिवस पर महिला एवं पुरुष वर्ग के प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न योग मुद्राओं एवं आसनों का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। प्रतिभागियों ने योग के माध्यम से शारीरिक क्षमता, मानसिक एकाग्रता, अनुशासन एवं आत्मनियंत्रण का परिचय दिया। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों का प्रदर्शन निर्धारित मानकों के आधार पर परखा गया।

प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में डॉ. अनुपम कोठारी, डॉ. राकेश कंडवाल एवं डॉ. भावना नेगी द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर अपने निर्णय दे कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्राचार्य प्रो. डी.एस. नेगी ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि योग भारतीय संस्कृति एवं परंपरा की अमूल्य धरोहर है। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक शांति, अनुशासन एवं सकारात्मक जीवनशैली विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

विशिष्ट अतिथि डॉ. पुष्कर गोड ने विश्वविद्यालय स्तर पर खेल एवं योग गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ–साथ उच्च स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर प्रदान करती हैं। कार्यक्रम का सफल संचालन एवं आयोजन क्रीड़ा समिति के संयोजक डॉ. हीरा सिंह डुंगरियाल के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रो. एस.सी. नौटियाल, प्रो. निरंजना शर्मा, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की बिभागध्यक्ष प्रो. ज्योति खरे, प्रो. इंदु तिवारी,. , प्रो. आर.के. द्विवेदी, प्रो. अरविंद अवस्थी, प्रो. मनीष डंगवाल, प्रो. एस.एस. बलूनी, डॉ. मीनाक्षी वर्मा, डॉ. संदीप किमोठी, डॉ. संदीप कुमार, डॉ. विनोद भंडारी, डॉ. जितेंद्र सिंह, डॉ. ऐश्वर्या राणा, डॉ. सुमन राणा, डॉ. विजय लक्ष्मी, डॉ. दया कृष्ण जोशी, डॉ. शेखर मेठाणी,डॉ. शशिबाला,बीजेएमसी प्राध्यापक अरविंद दुदपुड़ी, एवं मुकेश जदली सहित महाविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे। प्रतियोगिता समारोह का संचालन डॉ. जितेन्द्र, अंग्रेजी विभाग द्वारा किया गया। प्रतियोगिता का समापन 28 नवंबर को होगा, जिसमें विभिन्न वर्गों के विजेता प्रतिभागियों एवं टीमों के प्रदर्शन के आधार पर परिणाम घोषित किए जाएंगे।

संक्षिप्त समाचार

दिवंगत सैनिकों व परिजनों की स्मृति में 29 को होगा रक्तदान शिविर

जयन्त प्रतिनिधि।कोटद्वार : गुजरात के कच्छ में हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले कोटद्वार के वीर सैनिकों और उनके परिजनों की याद में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। डू समथिंग सोसाइटी और आधारशिला रक्तदान समूह की ओर से आयोजित इस शिविर में रक्तदान कर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। डू समथिंग सोसाइटी के संस्थापक मयंक प्रकाश कोठारी ने बताया कि रविवार, 29 नवंबर को दुर्गापुरी स्थित एमकेवीएन स्कूल में शिविर लगाया जाएगा। सुबह नौ बजे से शाम तीन बजे तक चलने वाले इस शिविर में क्षेत्रवासी स्वेच्छा से रक्तदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिविर के आयोजन का उद्देश्य दिवंगत सैनिकों और उनके स्वजनों की स्मृति को मानवता की सेवा से जोड़ना है। रक्तदान से किसी जरूरतमंद को नया जीवन मिल सकता है। ऐसे में रक्तदान के माध्यम से दिवंगतों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर रक्तदान करने की अपील की।

युवाओं को उद्यमिता के लिए किया प्रेरित

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय बनास पैठाणी में उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई), अहमदाबाद की संयुक्त पहल पर आयोजित आवासीय स्टार्ट अप बूट कैंप के दूसरे दिन छात्रों ने बिजनेस मॉडल और आइडिया पिचिंग प्रस्तुत किये।

इस मौके पर जिला समन्वयक डॉ. देवेंद्र सिंह चौहान ने बिजनेस मॉडलों का निरीक्षण कर बताया कि स्थानीय संसाधनों एवं जरूरतों पर आधारित विचारों को उद्यम विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। प्राचार्य प्रो. डॉ. विजय कुमार अग्रवाल ने युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित किया। ईडीआईआई विशेषज्ञ डॉ. रजत शर्मा ने व्यावसायिक विचारों का मूल्यांकन करते हुए उत्पाद की उपयोगिता, बाजार, लक्षित उपभोक्ताओं, लागत और लाभ के आकलन तथा प्रभावी पिचिंग के सुझाव दिए। इस मौके पर टिहरी जिला समन्वयक दिग्विजय सिंह, संयोजक डॉ. पुनीत चंद्र वर्मा, फैकल्टी मेंटर डॉ. प्रकाश फोंदणी, डॉ. कुमार गौरव जैन, डॉ. कामिका चौधरी, डॉ. उर्वशी, डॉ. आलोक कंडारी, डॉ. खिलाप सिंह आदि मौजूद रहे।

बाल विज्ञान कांग्रेस में अनन्या व जिया ने मारी बाजी

जूनियर और सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित


राजकीय इंटर कालेज कोटद्वार में आयोजित बाल विज्ञान कांग्रेस के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित करते अतिथि।

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच और नवाचार को मंच देने के उद्देश्य से आयोजित 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में जिले के नौनिहालों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में जूनियर हाईस्कूल रिगवाड़ी की अनन्या और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की जिया कैंत्यूरा ने अपने-अपने वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए किया गया है।

राजकीय इंटर कालेज कोटद्वार में आयोजित प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे विद्यार्थियों ने विज्ञान आधारित मॉडल और शोध परियोजनाएं प्रस्तुत कीं। प्रतियोगिता में बाल विज्ञानियों ने कचरा प्रबंधन, ऊर्जा, जल संचयन, दोहन, पुनर्चक्रण एवं संरक्षण, भोजन, कृषि, स्वास्थ्य और सतत विकास के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली जैसे विषयों पर अपने शोध प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता के प्राथमिक वर्ग में 35 और माध्यमिक वर्ग में 36 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। निर्णायक मंडल ने विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया। जूनियर वर्ग में जूनियर हाईस्कूल रिगवाड़ी की अनन्या ने प्रथम, जूनियर हाईस्कूल अमोला की अवनी ने द्वितीय और माउंट कार्मल स्कूल पाली पाबौ की अवशी मेवार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, सीनियर वर्ग में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की जिया कैंत्यूरा प्रथम, राइंका बनचूरी की सिमरन द्वितीय और राइंका गैंडखाल की राधिका तृतीय स्थान पर रही। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में अनीता बलोनी, कुसुम कोटनाला, मुकेश पटवाल, ज्योति ध्यानी, ऋतु उनियाल, रश्मि उनियाल, अजय बिष्ट, पूनम पटवाल, कल्पेश्वरी बलोदी और अमित कुमार शामिल रहे।

NAME CHANGE DECLARATION

I, Rohini, after marriage, am known as Rohini Devi, Wife of Subhash Chandra. Henceforth, I shall be known and identified as Rohini Devi.

ROHINI DEVI
W/o Subhash Chandra
Ward no-39,
Village & P.O. Jhandi Chaur East, Kotdwar,
District Pauri Garhwal,
Uttarakhand.
(0641/21)

फुटबाल में बाल भारती स्कूल का रहा दबदबा

आरसीडी मेमोरियल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का समापन, करीब 80 विद्यालयों के खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग

जयन्त प्रतिनिधि।कोटद्वार : शिवराजपुर स्थित आरसीडी पब्लिक स्कूल में आयोजित सात दिवसीय अंतरविद्यालयी आरसीडी मेमोरियल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का शुक्रवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता के दौरान फुटबाल के बालक और बालिका दोनों वर्गों में बाल भारती स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं, मेजबान आरसीडी पब्लिक स्कूल दोनों वर्गों में दूसरे स्थान पर रहा।

टूर्नामेंट में करीब 80 विद्यालयों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सात दिनों तक चली प्रतियोगिता में बास्केटबाल, वालीबाल और फुटबाल के मुकाबले आयोजित किए गए। प्रतियोगिता के पांचवें और छठवें दिन फुटबाल के रोमांचक मुकाबले हुए। बालक वर्ग में बाल भारती स्कूल ने प्रथम और आरसीडी पब्लिक स्कूल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में भी बाल भारती स्कूल प्रथम और आरसीडी पब्लिक स्कूल दूसरे स्थान पर रहा। वालीबाल प्रतियोगिता के बालक वर्ग में डैफोडिल्स स्कूल ने प्रथम, राइजिंग सन स्कूल ने द्वितीय और एमकेवीएन ने तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं, बालिका वर्ग में एमकेवीएन प्रथम और राइजिंग सन स्कूल द्वितीय स्थान पर रहा।

समापन समारोह में सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ऋषि कंडवाल ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधक नेहा कंडवाल ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और खेल प्रतिभा को निखारने के लिए विद्यालय की ओर से समय-समय पर इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा ढौंढियाल, निदेशक कपिल कंडवाल, कनिष्का ढौंढियाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सैन्य अभिलेखों में मेरी पत्नी पुष्पा रावत की जन्मतिथि 21/06/1978 एवं मेरी पुत्री मानसी रावत की जन्मतिथि 29/05/2006 अंकित है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पत्नी पुष्पा रावत की वास्तविक जन्मतिथि 06/02/1978 एवं मेरी पुत्री मानसी रावत की वास्तविक जन्मतिथि 11/01/2003 है। अतः मेरे सैन्य अभिलेखों में मेरी पत्नी पुष्पा रावत की वास्तविक जन्मतिथि 06/02/1978 एवं मेरी पुत्री मानसी रावत की वास्तविक जन्मतिथि 11/01/2003 दर्ज की जाय।

आर्मी नंबर- G/2501661F
Hav GD हरेन्द्र सिंह रावत पुत्र स्व0 प्रताप सिंह रावत निवासी घमण्डपुर, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
(0640/21)

उत्तर रेलवे
ई–नीलामी सूचना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/पीएस (ए.सी.ओ.), उत्तर रेलवे, मुरादाबाद मंडल के द्वारा अर्धकुम्भ मेला–2027 के लिए मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशनों पर अस्थायी कैटरिंग ट्रॉलियों के आवंटन हेतु कोटेशन के आधार पर दिनांक **12.12.2026** को ई–नीलामी के माध्यम से कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तें **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध हैं। **4125/2026**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे
निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियन्ता/समन्वय द्वारा ई टेन्डर जिनके बन्द होने की तिथि प्रत्येक निविदा के सामने अंकित है। निम्न टेन्डर संख्या के अर्न्तगत आंमत्रित किये जाते हैं जो उसी दिन 16:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। निविदा की कीमत तथा धरोहर राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, केडिट कार्ड आदि के माध्यम से आनलाइन भुगतान करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, डिपाजिट रसीद आदि स्वीकार्य नहीं होंगे। टेन्डर से संबंधित अन्य जानकारी वैबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखें।

टेन्डर संख्या दिनांक	261-DRM-MB-26-27 Dt. 27.11.2026
कार्य का नाम	Annual maintenance contract (AMC) for GPS tracking devices over Moradabad division under Sr DEN/C/MB.
निविदा का प्रकार	Service
निविदा की कीमत	3,000.00
अनुमानित लागत	46,94,374.22
धरोहर राशि	93,900.00
टेन्डर क्लोसिंग दिनांक / समय	12.12.2026 16:00
बिडिंग स्टार्ट तिथि	28.11.2026
आफर की वैधता	60 Days
कार्य पूर्ण करने की अवधि	24 Months

नं.: 74-W/2/3/WA/Publication दिनांक: 27.11.2026 **4145/2026**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

सतपुली महाविद्यालय में स्व-गणना का दिया प्रशिक्षण


राजकीय महाविद्यालय सतपुली खैरासैण में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में जानकारी देते हुए प्रशिक्षक।

जयन्त प्रतिनिधि। सतपुली : राजकीय महाविद्यालय सतपुली खैरासैण में स्व-गणना के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक द्वारा ऑनलाइन स्वगणना की प्रक्रिया का चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किया गया। प्रतिभागियों को ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश करने, आवश्यक जानकारियां भरने, निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने, स्व-गणना की प्रक्रिया को सफलता पूर्वक पूर्ण करने के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित अनिल कुमार बिष्ट व दीपक काला ने स्व-गणना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्व-गणना की अवधारणा, उद्देश्य, उपयोगिता एवं इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को सरल एवं व्यावहारिक ढंग से समझाया। उन्होंने बताया कि स्व-गणना के माध्यम से व्यक्ति स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित विवरण दर्ज कर सकता है। इससे गणना प्रक्रिया को अधिक सरल, सुगम एवं व्यवस्थित बनाने में सहायता मिलती है। साथ ही, स्व-गणना करते समय बरती जाने वाली सावधानियों एवं सही जानकारी दर्ज करने के बारे में बताया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं, प्राध्यापकों एवं महाविद्यालय के समस्त कर्मचारियों को स्व-गणना की प्रक्रिया, उसके महत्व, ऑनलाइन माध्यम से स्वगणना करने की विधि से अवगत कराना था। कार्यशाला में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. संजय कुमार, नोडल डॉ. संजीव कुमार आदि मौजूद थे।

उत्तर रेलवे
(मुरादाबाद मण्डल)
निविदा सूचना

क्र सं.	कार्य का नाम एवं लोकेशन	कार्य की अनुमानित लागत (रु.)	कार्यालय का पता जहाँ से निविदा प्रपत्र जारी किया गया है	बिड सिक्यूरिटी राशि (रु.)	कार्य के पूर्ण करने की समय अवधि	निविदा प्रपत्र जमा करने तथा खुलने की दिनांक व समय	वेबसाइट एवम कार्यालय का पता
1	46/वरिष्ठ मं.वि.अभि./सा./मुरा./2026 हरिद्वार क्षेत्र में कुंभ मेला–2027 के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए DG सेट किराए पर लेना हेतु विद्युत कार्य।	4046601.60 (जीएसटी सहित)	विद्युत शाखा, मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद	80900.00	120 (एक सौ बीस) दिन	निविदाये दिनांक 18.12.2026 को 15:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन 15:00 बजे खोली जायेगी।	वेबसाइट www.ireps.gov.in मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय/उत्तर रेलवे मुरादाबाद

निविदा सूचना सं. : 39/2026 दिनांक : 26.11.2026 **4112/2026**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

बेटी की जिद और जनसहयोग ने लिखी घर वापसी की कहानी

2.51 करोड़ जुटाकर पिता को सऊदी अरब से छुड़ाया

जगमोहन डांगी।

पौड़ी : कहते हैं कि जब किसी बेटी का संकल्प मजबूत हो तो मुश्किल से मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही मिसाल उत्तरकाशी के गाजणा क्षेत्र के गोरसाड़ा गांव की बेटी दीपिका नौटियाल ने पेश की है। पिता को सऊदी अरब से सकुशल भारत वापस लाने के लिए दीपिका ने जो संघर्ष शुरू किया था, आखिरकार शुक्रवार को वह मुकाम तक पहुंच गया। लंबे समय से सऊदी अरब में कानूनी प्रक्रिया में उलझे इंद्रमणि नौटियाल शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंच गए। उनके भारत लौटते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और अपनों से मिलने का वर्षों पुराना इंतजार खत्म हो गया।



इंद्रमणि नौटियाल वर्ष 2018 में परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने और रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए थे। वहां रियाद की एक निजी कंपनी में वह ट्रक चालक के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन वर्ष 2019 में एक सड़क दुर्घटना ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उनके ट्रक की एक कार से टक्कर हो गई थी। इस हादसे में कार सवार पांच सऊदी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। दुर्घटना के बाद इंद्रमणि को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। सऊदी अरब की अदालत ने उन्हें करीब एक वर्ष की कैद की सजा सुनाई। उन्होंने जेल की सजा पूरी कर ली, लेकिन मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। दुर्घटना के समय ट्रक का बीमा नहीं होने के कारण अदालत ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए 9 लाख 84 हजार सऊदी रियाल जमा कराने का आदेश दिया। भारतीय मुद्रा में यह राशि करीब 2.51 करोड़ रुपये थी। इतनी बड़ी रकम जुटाना इंद्रमणि के परिवार के लिए लगभग असंभव था। नतीजतन, सजा पूरी होने के बावजूद उनकी रिहाई और स्वदेश वापसी की राह अटकी रही।

पिता की घर वापसी के लिए बेटी ने छेड़ी मुहिम

पिता को वापस लाने की उम्मीद में बेटी दीपिका नौटियाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के दरवाजे खटखटाए। इसके साथ ही सोशल मीडिया को अपनी आवाज का माध्यम बनाया और देशभर के लोगों से आर्थिक सहयोग की अपील की। एक बेटी की इस भावुक अपील ने लोगों के दिलों को छू लिया। उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव से शुरू हुई मदद की यह मुहिम धीरे-धीरे देश के अलग-अलग राज्यों और विदेशों तक पहुंच गई।

छोटे-छोटे सहयोग से जुटे 2.51 करोड़ रुपये

दीपिका की अपील पर ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों, प्रवासी भारतीयों और देश-विदेश में रहने वाले हजारों लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया। किसी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटी राशि दी तो किसी ने बड़ी मदद कर इस अभियान को मजबूती दी। उत्तराखंड सरकार की ओर से भी दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। इस पूरे अभियान में टिहरी निवासी अंतरराष्ट्रीय समाजसेवी रोशन रतूड़ी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने धनराशि जुटाने के साथ-साथ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराने में सहयोग किया। उनके अनुसार, दुर्घटना के समय ट्रक का बीमा नहीं था और अदालत ने 9 लाख 84 हजार सऊदी रियाल मुआवजा जमा कराने का आदेश दिया था। करीब दो महीने तक चले लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार जरूरी धनराशि जुटा ली गई।

छः साल की परेशानी के बाद अपनों के बीच लौटे इंद्रमणि

आवश्यक मुआवजे की रकम जमा होने के बाद सऊदी अरब में रिहाई से संबंधित कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं। इसके बाद इंद्रमणि की भारत वापसी का रास्ता साफ हुआ। शुक्रवार सुबह उनके दिल्ली पहुंचने की खबर मिलते ही परिजनों और गांव में खुशी का माहौल बन गया। इंद्रमणि की यह घर वापसी केवल एक परिवार की खुशी नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना, जनसहयोग और एक बेटी के अटूट संकल्प की मिसाल बन गई है। दीपिका ने साबित कर दिया कि मुश्किल परिस्थितियों में हिम्मत और विश्वास के साथ उठाई गई आवाज बेअसर नहीं जाती। हजारों लोगों के छोटे-बड़े सहयोग ने एक परिवार को फिर से मिलाने में अहम भूमिका निभाई और गोरसाड़ा गांव की इस बेटी का संघर्ष अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया है।

दो दिनों में 61 मीटर से अधिक लंबाई की कच्ची सड़क बनाई



कर्णप्रयाग। विकासखंड के रवेंठा, मोली, रोलजुन्यारी आदि गांवों के ग्रामीण श्रमदान से सड़क निर्माण के कार्य में दूसरे दिन भी जुटे रहे। ग्रामीणों दूसरे दिन 23 मीटर से अधिक लंबाई की कच्ची सड़क बनाई। दो दिनों में ग्रामीण 61 मीटर से अधिक लंबी सड़क खोद चुके हैं। वहीं शुक्रवार को वन विभाग की टीम भी निर्माण स्थल पर पहुंची एवं घटना का जायजा लिया। कांचुला–गैना संजाकटा सड़क का तीन किमी से अधिक हिस्से के निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। इस हिस्से के निर्माण होने से गनोली ग्राम पंचायत के रवेंठा, मोली एवं रोलजुन्यारी आदि गांवों को लाभ मिलता। लगातार मांग के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर ग्राम प्रधान कुसुम पुंडीर, महिला मंगल दल एवं युवक मंगल दल के नेतृत्व में बृहस्पतिवार से ग्रामीण सड़क निर्माण के कार्य में जुटे हैं। ग्रामीण दर्शन सिंह पुंडीर ने बताया कि दो दिनों में ग्रामीण करीब 9 फीट चौड़ी एवं 61 मीटर लंबी कच्ची सड़क खोदकर बना चुके हैं। सड़क की समस्या से परेशान बुजुर्ग, दिव्यांग सहित 45 से अधिक ग्रामीण सड़क निर्माण के कार्य में लगे हैं। वहीं सूचना पर शुक्रवार को वन दरोगा नरेंद्र सिंह एवं वन वीट अधिकारी संदीप सिंह मौके पर पहुंचे। वन दरोगा नरेंद्र सिंह ने बताया कि निरीक्षण की रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को सौंपी जाएगी।

विद्यार्थियों को दिया आपदा सुरक्षा का प्रशिक्षण

चिन्यालीसौड़/पुरोला। राज्य आपदा प्रबंधन दिवस पर बिरजा इंटर कॉलेज चिन्यालीसौड़ में एसडीआरएफ की ओर से आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण एवं मॉक अभ्यास आयोजित किया गया। इसमें 531 छात्र–छात्राओं और 37 शिक्षकों व कर्मचारियों सहित कुल 568 लोगों ने प्रतिभाग किया।आपदा प्रबंधन मास्टर ट्रेनर सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में एसडीआरएफ चिन्यालीसौड़ की टीम ने छात्राओं को भूकंप, बाढ़, वनाग्नि और अन्य आपदाओं से बचाव के तरीके बताए। इस दौरान खोज एवं बचाव उपकरणों के उपयोग, घायलों को प्राथमिक उपचार देने, सीपीआर और स्थानीय संसाधनों से अस्थायी स्ट्रेचर बनाने का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। वही अग्निशमन विभाग पुरोला की ओर से स्थानीय संस्कृत विद्यालय में अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभाग के प्रभारी मुन्ना सिंह चौहान, गिरीश रावत और अमित कुमार ने छात्राओं को गैस सिलिंडर, बिजली के उपकरणों और शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग से बचाव के तरीके बताए।

12 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन



जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल के तत्वावधान में आगामी 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल सहित जनपद के समस्त बाह्य न्यायालयों में किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धन वसूली एवं पैसे के लेन–देन से संबंधित मामले, श्रम एवं नियोजन विवाद, वैवाहिक विवाद, किरायेदारी, व्यादेश एवं विनिर्दिष्ट अनुपालन से संबंधित दीवानी वाद, चेक अनादरण (धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम), मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, राजस्व वाद, उपभोक्ता आयोग में लंबित वाद तथा बैंकों के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों सहित अन्य सुलह योग्य मामलों का निस्तारण आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिकाधिक वादों के निस्तारण के उद्देश्य से शुक्रवार को माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल धर्म सिंह की अध्यक्षता में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं अधिवक्ताओं के साथ प्री-लोक अदालत बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों के निस्तारण हेतु संबंधित पक्षों के मध्य आपसी समन्वय स्थापित करने, मामलों में सुलह-समझौते की संभावनाओं को बढ़ाने तथा राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों के निस्तारण हेतु आवश्यक विचार-विमर्श किया गया। बैठक में आमजन से राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने सुलह योग्य मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से कराकर शीघ्र, सुलभ एवं कम खर्चीला न्याय प्राप्त करने का लाभ उठाने की अपील की। बैठक में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल कमल प्रसाद बमराड़ा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल के रिटेनर अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह रावत सहित विभिन्न बीमा कंपनियों के अधिवक्ता एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

चमोली में आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्रों के लिए 36 पदों पर भर्ती

कर्णप्रयाग। जिले के नौ विकासखंडों में संचालित 18 आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्रों के लिए महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने 36 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें क्रेच वर्कर के 18 और क्रेच हेल्पर के 18 पद शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 17 दिसंबर तक संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में केवल पंजीकृत डाक से आवेदन भेज सकते हैं। कर्णप्रयाग, दशोली, नारायणबगड़, पोखरी, नंदानगर, ज्योतिर्मठ, गैरसैंण, थराली और देवाल ब्लॉक के दो–दो केंद्रों में भर्ती की जाएगी। इनमें पीलसेरा और प्रेम बहुगुणा नगर, सुभाषनगर–2 और विवेकानंद कॉलोनी, नारायणबगड़ और मैदुनी, जिलासू और पोखरी–2, कुरुड़ और कुन्तरी फाली, नागचोडारी और डाडों, गैर–2 और धारगट, कुलसारी और राड़ीबगड़ तथा सैलखोला और देवाल शामिल हैं। क्रेच वर्कर के लिए इंटरमीडिएट और हेल्पर के लिए हाईस्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन शैक्षिक योग्यता की मेरिट के आधार पर होगा। चयनित क्रेच वर्कर को 5500 रुपये और हेल्पर को 3000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। आवेदन के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन और चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिला कार्यक्रम अधिकारी हिमांशु बडोला ने बताया कि आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय और जिला कार्यक्रम कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

तीन साल बाद भी नहीं मिली सेवानिवृत्ति की धनराशि

उत्तरकाशी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद से सेवानिवृत्त हुए तीन साल बीतने के बाद भी उन्हें धनराशि नहीं मिल पा रही है। आर्थिक तंगी और खराब स्वास्थ्य से जूझ रही कार्यकर्ता को उपचार कराने में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में उन्होंने जिलाधिकारी से गुहार लगाकर लंबित धनराशि का जल्द भुगतान कराने की मांग की है। जिलाधिकारी को सौंपे प्रार्थनापत्र में बौन गांव निवासी पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चंद्रा देवी ने बताया कि वह करीब तीन वर्ष पूर्व अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुकी है। नियमानुसार सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली धनराशि के लिए उन्होंने कई बार प्रयास किए लेकिन अब तक उन्हें भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उपचार की आवश्यकता है। चंद्रा देवी ने कहा कि लंबे समय तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली धनराशि उनके लिए आर्थिक सहारा है लेकिन तीन साल से भुगतान लंबित होने के कारण उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है।

राजमिस्त्री का बेटा बना सेना में अफसर, बिना कोचिंग पास की एनडीए परीक्षा

नारायणबगड़। विकासखंड के सुदूरवर्ती गांव बमियाला निवासी हिमांशु पंवार ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बिना किसी कोचिंग के उन्होंने पहले ही प्रयास में एनडीए परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय सेना में अफसर बनने का गौरव हासिल किया है। उनकी सफलता से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। हिमांशु की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुई। उन्होंने हाईस्कूल श्रीनंदा देवी जनता इंटर कॉलेज कफोली और इंटरमीडिएट जीआईसी नारायणबगड़ से उत्तीर्ण किया।

इसके बाद वे अपने मामा रणजीत सिंह के पास देहरादून चले गए। उन्होंने लाइब्रेरी में नियमित अध्ययन कर एनडीए की तैयारी की और पहले प्रयास में सफलता प्राप्त की। हिमांशु के पिता गजे सिंह पंवार राजमिस्त्री हैं जबकि माता रामी देवी गृहिणी हैं। दो बहनों के इकलौते भाई हिमांशु की इस उपलब्धि पर ग्राम प्रधान हिमानी देवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य विनीता देवी, शिक्षक दलवीर सिंह पंवार और कृपाल सिंह सहित क्षेत्रवासियों ने खुशी जताई।

देवेन्द्र पींचा ने संभाली पौड़ी जिले की कमान

जनपद की कानून व्यवस्था एवं पुलिसिंग की प्राथमिकताओं पर की चर्चा



जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : शुक्रवार को नव नियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पींचा ने एसएसपी पौड़ी गढ़वाल के पद का विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व गार्द ने उन्हें सलामी दी। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर विभिन्न शाखाओं एवं इकाइयों की कार्यप्रणाली, जनपद की वर्तमान कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं पुलिसिंग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बेहतर समन्वय, अनुशासन, जवाबदेही एवं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कर्तव्यों का निर्वहन करने पर बल दिया। इस दौरान एसएसपी ने पुलिस कार्यालय की समस्त शाखाओं का भ्रमण कर प्रत्येक शाखा में संचालित कार्यों एवं कार्यालयी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देवेन्द्र पींचा वर्ष 2016 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी हैं। अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए पुलिस प्रशासन, कानून-व्यवस्था एवं जनसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुभव अर्जित किया है। इससे पूर्व वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा, सेनानायक 31वीं वाहिनी पीएसी, पुलिस अधीक्षक चंपावत, एसपी क्राइम एवं ट्रैफिक नैनीताल, अपर पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंह नगर सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जनपद पुलिस कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता एवं टीम भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गजल्ड गांव से भालू को भगाने में वन विभाग को मिली सफलता

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : वन विभाग की टीम को गजल्ड गांव से भालू को भगाने में सफलता मिली है। बीते बृहस्पतिवार को गांव के आस पास ही भालू दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत बढ़ गई थी। ठंड बढ़ने से गांवों के समीप लागातार जंगली जानवरों की चहल कदमी से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। सांय होते ही ग्रामीण घरों में कैद होने को मजबूर है। वन विभाग द्वारा गुलदार प्रभावित गजल्ड, चवथ, ओजली, बाड़ा, बमठी आदि गांवों में सर्तकता और जनसुरक्षा के लिए ग्राम स्वयं सेवक सुरक्षा दल का गठन किया जा रहा है। विभाग की ओर से 18 से 20 युवाओं की टीम का गठन किया जाएगा। विभाग स्वयं सेवकों को जरूरी सामान मुहैया करायेगा। साथ ही युवाओं को गुलदार व भालू से



सर्तक और जनसुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव ने बताया कि ठंड के मौसम में वन्यजीवों के हमलों का खतरा अधिक होता है। बताया कि वन्यजीवों के हमलों का पैटर्न भी बदलता जा रहा है। पहले वन्यजीवों के हमले रात 7 से 8 बजे अधिक होते थे, वहीं अब ये शाम ढलते ही सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सहभागिता से इन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है।

गौचर में सार्वजनिक पुस्तकालय का अभाव

कर्णप्रयाग। तेजी से विकसित होते गौचर नगर में सार्वजनिक और निजी पुस्तकालयों का अभाव है। ऐसे में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) ने युवाओं के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की है। इसमें पांच हजार से अधिक किताबें उपलब्ध हैं। बाहरी युवा व आम लोग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक यहां आकर पढ़ाई कर सकते हैं।

रेलवे और हवाई कनेक्टिविटी वाले इस नगर में पॉलीटेक्निक, आईटीबीपी, डायट सहित कई संस्थान कार्यरत हैं लेकिन यहां कोई भी सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं है। कोविड के बाद यहां डायट ने पुस्तकालय की सुविधा लोगों को दी है। डायट के पुस्तकालय प्रभारी डॉ. कमलेश कुमार मिश्र का कहना है कि पुस्तकालय में करीब 5 से 7 हजार पुस्तकें हैं। यहां करीब 30 से 40 लोग बैठकर पढ़ सकते हैं। यहां से किताबें बाहर नहीं दी जाती हैं। पुस्तकालय में अधिकतर युवा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे ही पढ़ने आते हैं।

करीब 30 से 35 बच्चे रोज यहां पढ़ते हैं। कुछ अपनी किताबें और लैपटॉप लेकर भी पढ़ते हैं। कुछ को संस्थान की किताबें भी मदद करती हैं। पुस्तकालय में सभी चीजें दुरुस्त रहे इसके लिए 50 रुपये प्रतिमाह और 100 रुपये सदस्यता का न्यूनतम शुल्क रखा गया है। जगह कम होने के चलते इसका विस्तार नहीं हो पा रहा है।

चमोली में बड़ा हादसा होने से बचा: बच्चे ने गलती से दबाया सेल्फ बटन

चमोली। थराली क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक बड़ा हादसा होते–होते बच गया। बागेश्वर से आए पांच लोगों की मैक्स टैक्सी सड़क से करीब 30 मीटर नीचे नदी किनारे जा गिरी। हादसे के समय वाहन में एक बच्चा बैठा हुआ था, जबकि चालक समेत चार लोग नदी किनारे पूजा करने गए थे। इस दौरान बच्चे ने गलती से सेल्फ बटन दिया। जिससे वाहन नदी किनारे जा गिरा। गनीमत रही कि हादसे में बच्चा बाल–बाल बच गया।



जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे मैक्स वाहन सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान वाहन में बैठे बच्चे ने गलती से गाड़ी का सेल्फ दबा दिया। इससे वाहन अचानक स्टार्ट होकर अनियंत्रित हो गया और सड़क से करीब 30 मीटर नीचे नदी किनारे जा लुढ़का। राहत की बात यह रही कि नीचे पहुंचने के बाद वाहन सीधा खड़ा हो गया और उसमें बैठा बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रहा। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय निवासी प्रेम बुटोला, हरपाल सिंह, कुंवर सिंह और जयवीर सिंह मौके पर पहुंचे। इसके बाद लोनिवि के जेसीबी ऑपरेटर अनिल डिमरी ने अस्थायी रास्ता तैयार कर वाहन को सड़क तक पहुंचाने में मदद की। वाहन को सुरक्षित निकालने के बाद सभी पांचों लोग सकुशल बागेश्वर लौट गए।

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म करने का प्रस्ताव पारित

गोपेश्वर। जिले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के अटैचमेंट समाप्त करने के लिए जिला पंचायत शासन को प्रस्ताव भेजेगी। शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में अध्यक्ष दौलत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सदस्यों ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताते हुए अटैचमेंट व्यवस्था खत्म करने का मुद्दा उठाया। सदन ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजने का निर्णय लिया।

बैठक में सदस्यों ने कहा कि प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। गर्भवतियों को कई किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचना पड़ता है और कई बार रास्ते में ही प्रसव की स्थिति बन जाती है। जिले के अन्य अस्पतालों में भी उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। सदस्यों ने महिला बेस अस्पताल सिमली को डिलीवरी सेंटर के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात एएनएम को दूसरे जिलों में अटैच किए जाने पर आपत्ति जताई।

इस पर सीएमओ डॉ. राजीव पाल ने बताया कि कर्मचारियों के अटैचमेंट शासन स्तर से किए जाते हैं। इसके बाद सदन ने अटैचमेंट व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। वन विभाग की समीक्षा में सदस्यों ने वन्यजीवों के हमलों में मवेशियों के मारे जाने और लोगों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के डीएफओ रजत सुमन ने मुआवजा प्रक्रिया और वन्यजीवों से बचाव के लिए किए जा रहे सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी दी।

ईओ के रवैये से नाराज पालिकाध्यक्ष 18 दिन से धरने पर

चिन्यालीसौड़। जनहित और जरूरी सरकारी कार्यों में अधिशासी अधिकारी का अपेक्षित सहयोग नही मिलने से नाराज नगर पालिकाध्यक्ष मनोज कोहली ने विरोध का अनूठा तरीका अपनाया है। वे पिछले 18 दिनों से पालिका कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। पालिकाध्यक्ष ने नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन से यह विरोध शुरू किया था। उनका कहना है कि ईओ के असहयोगात्मक रवैये के कारण नगर क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण जनहित के कार्य लंबित पड़े है। इस संबंध में उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय और डीएम को भी अवगत कराया है। अध्यक्ष ने बताया कि बड़ेथी बनचौरा मार्ग पर जल निकासी की व्यवस्था, जाम से निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाने, बीआरओ के ऑलवेदर सड़क बाईपास पर जल निकासी और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का सुधारीकरण जरूरी है।

नौगांव में 304 किसानों को बांटे 2.74 करोड़ के ऋण चेक

नौगांव (उत्तरकाशी)। जिला सहकारी बैंक एवं सहकारिता विभाग की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किसान ऋण मेले में 304 काश्तकारों को कुल 2 करोड़ 74 लाख 82 हजार रुपये के ऋण चेक वितरित किए गए। इस दौरान किसानों को बैंक और सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। ब्लॉक सभागार में आयोजित किसान ऋण मेले का शुभारंभ जिला सहकारी बैंक की अध्यक्ष शारदा राणा और राज्य मंत्री श्याम डोभाल ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर बैंक की अध्यक्ष शारदा राणा ने कहा कि जिला सहकारी बैंक किसानों और ग्राहकों के लिए ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि नौगांव विकासखंड में संचालित तीन सहकारी बैंकों के माध्यम से 304 काश्तकारों को 2.74 करोड़ से अधिक के ऋण चेक वितरित किए गए। उन्होंने किसानों से सहकारी बैंक और समितियों की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। इस मौके पर महाप्रबंधक किशोर कुमार, शाखा प्रबंधक स्वाति भंडारी, रविंद्र रावत, पूर्व विधायक मालचंद, केदार सिंह रावत, विजय बंधानी मौजूद रहीं।

संक्षिप्त समाचार

मिस्र में तेल टैंकर में आग, 31 की मौत:21 से ज्यादा घायल; कई गाड़ियां भी जलीं



काहिरा, एजेंसी। मिस्र की राजधानी काहिरा के पास हाईवे पर बुधवार रात एक तेल टैंकर में आग लग गई। इसकी चपेट में आने से 24 से ज्यादा कारें और बाइक जल गईं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 से ज्यादा घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया था। इसके बाद उसमें जोरदार धमाका हुआ और आग फैल गई। जलती गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। स्थानीय लोगों ने भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। अब आग पर काबू पा लिया गया है। हादसा काहिरा के उपनगर इम्बाबा के वाराक जिले में हुआ, जहां आग तेजी से कई कारों में फैल गई। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल-फतह अल-सीसी ने पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई। घायलों को जायद स्पेशलाइज्ड, इम्बाबा जनरल और वर्राक सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बचाव अभियान में 39 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। मिस्र में हर साल सड़क हादसों में हजारों लोगों की मौत होती है। तेज रफ्तार, खराब सड़कों और ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन न होना इन दुर्घटनाओं की प्रमुख वजह हैं। इसी साल जनवरी में बेनी सुएफ प्रांत के पास कई गाड़ियों की भीषण टक्कर में 21 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 16 घायल हुए थे।

नाइजीरिया में 22.6 करोड़ डॉलर की मेथामफेटामाइन जब्त

नाइजीरिया , एजेंसी। नाइजीरिया की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसी ने बुधवार को देश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में बड़ी कार्रवाई करते हुए कम से कम 22 करोड़ डॉलर मूल्य की मेथामफेटामाइन जब्त की। इस मामले में पांच मैक्सिकन नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। नेशनल इ्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने बताया कि उसके अधिकारियों ने एनुगु राज्य में बड़े पैमाने पर चल रही एक अवैध प्रयोगशाला पर छापा मारा। यहां से मेथामफेटामाइन बनाने में विशेषज्ञता रखने वाले पांच मैक्सिकन नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। एजेंसी के प्रवक्ता फेमी बाबाफेमी ने एक बयान में बताया कि इन लोगों को कथित तौर पर एक नाइजीरियाई नागरिक ने भर्ती किया था। वे फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश में दाखिल हुए थे। बाबाफेमी ने कहा, 'अवैध रूप से संचालित इस फैक्टरी से कुल 1,512 किलोग्राम मेथामफेटामाइन बरामद की गई। इसमें तैयार और निर्माणाधीन दोनों तरह की नशीली दवाएं शामिल हैं। इनकी अनुमानित कीमत 22.68 करोड़ डॉलर है। इस साल देश में की गई सबसे बड़ी जब्तियों में से यह एक है। नाइजीरिया अवैध मादक पदार्थों के कारोबार का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। इसी साल मई में दक्षिण-पश्चिमी नाइजीरिया में नाइजीरियाई और मैक्सिकन नागरिकों से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था। हाल के दिनों में इस तरह की कई कार्रवाइयां की गई हैं।

जापान : जंगली सब्जियों के लिए हजारों डॉलर खर्च कर रहे लोग

टोक्यो, एजेंसी। ऑर्गेनिक खानपान और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति बढ़ते वैश्विक रुझान ने जापान की सदियों पुरानी जंगली सब्जियां चुनने की परंपरा को नया आकर्षण बना दिया है। यहां पर्यटक जंगलों और पहाड़ों में प्राकृतिक रूप से उगने वाली सब्जियां जुटाने के लिए विशेष टूर और कार्यशालाओं पर सैकड़ों से लेकर हजारों डॉलर तक खर्च कर रहे हैं। 'सानसाई' नाम से पहचानी जाने वाली इन मौसमी पहाड़ी सब्जियों के प्रति दिलचस्पी बढ़ रही है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में सानसाई की परंपरा हजारों साल पुरानी है। वसंत ऋतु में पहाड़ों और जंगलों में उगने वाले इन पौधों की 280 से अधिक किस्में बताई जाती हैं।

अमेरिका ने 10 लाख एआई उपग्रहों के लिए स्पेसएक्स की योजना को मंजूरी दी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी नियामकों ने स्पेसएक्स को अंतरिक्ष में डेटा सेंटर के रूप में काम करने वाले 10 लाख तक उपग्रह तैनात करने की अनुमति दे दी है। खगोलविदों ने इस पर आपत्ति जताई है और चेतावनी दी है कि इस परियोजना से शोध कार्यों में बाधा आ सकती है और रात को आसमान का स्वरूप बदल सकता है। फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (एफसीसी) ने कहा कि प्रस्तावित 'स्टारमाइंड' नेटवर्क पृथ्वी पर इस्तेमाल के लिए अंतरिक्ष में डेटा प्रोसेस करेगा, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसे अंतरिक्ष में डेटा सेंटरों के एक समूह के लिए अमेरिका की ओर से दी गई पहली मंजूरी बताया गया है। इस मंजूरी से नेटवर्क को स्थापित करने की अनुमति मिलती है; इसका मतलब यह नहीं है कि उपग्रह (पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं।

ये उपग्रह ऑप्टिकल लिंक के जरिए कम्युनिकेट करेंगे, जबकि रेडियो लिंक बैकअप और आपातकालीन संचार के रूप में काम करेंगे। एफसीसी ने कहा कि यह सिस्टम अंतरिक्ष में मौजूद कचरे से जुड़े उनके नियमों के अनुरूप है।

चेयरमैन ब्रेंडन कैर ने कहा, 'अमेरिका दुनिया को 'सुपर इंटेलिजेंस' के युग में ले जा रहा है।



राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में, अमेरिका यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है कि यह क्रांतिकारी तकनीक नए अवसर पैदा करे, निवेश को बढ़ावा दे और अमेरिकी लोगों को लंबे समय तक लाभ पहुंचाए। '

उन्होंने कहा, 'एफसीसी ने आज अंतरिक्ष में डेटा सेंटरों के लिए 10 लाख 'ऑर्बिटल कंप्यूट मॉड्यूल' तैनात करने की मंजूरी देकर इस प्रयास को और तेज कर दिया है। यह कदम अमेरिका के नेतृत्व और विकास को गति देने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नई और साहसिक शुरुआत है। '

कैर ने कहा, 'सुपर इंटेलिजेंस (एसआई) के क्षेत्र में अमेरिका के नेतृत्व को बनाए रखने के लिए 'कंप्यूट कैंपस' या डेटा सेंटर बहुत जरूरी हैं। अपनी कंप्यूटिंग क्षमता को पृथ्वी से बाहर ले जाकर, स्पेसएक्स और उनके कई प्रतिस्पर्धी, जो अपने खुद के ऑर्बिटल डेटा सेंटरों पर काम कर रहे हैं, समय की मांग को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, 'यह अमेरिकी सूझबूझ का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो अंतरिक्ष और उन्नत तकनीक में हमारी ताकतों को एकजुट कर सकता है, हमारी आर्थिक बढ़त को मजबूत कर सकता है और हमारे देश में समृद्धि का विस्तार कर सकता है। एफसीसी ने बताया कि वह अंतरिक्ष में डेटा सेंटरों से जुड़े अन्य प्रस्तावों की भी समीक्षा कर रहा है और अपनी नियमित प्रक्रियाओं के तहत उन पर जल्द ही फैसला लेगा। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी' ने इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि वे इस मंजूरी से 'बहुत निराश और हताश' हैं। सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि बड़े और अधिक संख्या में मौजूद उपग्रह लंबे समय तक चमकते रह सकते हैं, जिससे खगोलीय अवलोकन में बाधा आ सकती है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटिंग उपकरणों से निकलने वाला रेडियो उत्सर्जन और गर्मी, रेडियो और इन्फ्रारेड खगोल विज्ञान को भी प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, उन्होंने अंतरिक्ष में उपग्रहों के आपस में टकराने और लॉन्चिंग तथा वायुमंडल में दोबारा प्रवेश के कारण होने वाले प्रदूषण को लेकर भी चिंता जताई है। एक मीडिया बयान में कहा गया है, 'अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी (एएएस) इस बात से निराश और दुखी है कि फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने स्पेसएक्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में दस लाख (1 मिलियन) उपग्रहों का एक नेटवर्क तैनात करने का लाइसेंस दे दिया है। बयान में कहा गया है, 'जैसा कि एएएस ने पहले भी एफसीसी के सामने अपनी बात रखी थी, यह प्रस्तावित नेटवर्क (द्व) खगोलीय सुविधाओं में दशकों से किए गए सरकारी निवेश को काफी नुकसान पहुंचाएगा, और (द्वद्व) खगोलविदों तथा आम लोगों की रात के आसमान को देखने और उसका अध्ययन करने की क्षमता को प्रभावित करेगा। ' सोसाइटी ने माना कि स्पेसएक्स ने पहले खगोल विज्ञान पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए अपने 'स्टारलिंक' उपग्रहों के डिजाइन में बदलाव किए थे। सोसाइटी के अनुसार, इन बदलावों से कुछ मदद तो मिली, लेकिन समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुईं। उन्होंने दस लाख उपग्रहों वाले इस प्रस्तावित नेटवर्क को एक बिल्कुल अलग स्तर का प्रोजेक्ट बताया। सोसाइटी के अनुसार, इस लाइसेंस की शर्तों के तहत स्पेसएक्स को 2033 तक उपग्रह तैनात करना शुरू करना होगा, 2035 तक कक्षा में 1 लाख उपग्रह स्थापित करने होंगे, और 2040 तक पूरे नेटवर्क को तैनात करना होगा।

ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका: जन्म से नागरिकता छीनने की नई कोशिश पर लगाई रोक; जानें फैसले में क्या-क्या कहा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता देने के नियमों में बदलाव करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक और कोशिश को अदालत ने रोक दिया है। वॉशिंगटन की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन के नए आदेश पर रोक लगाते हुए साफ कहा कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अमेरिकी संविधान में दिए गए नागरिकता के अधिकार में नई शर्तें नहीं जोड़ सकते। इस मामले में अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन ने प्रभावित परिवारों की ओर से अदालत में याचिका दायर की थी।

यह मामला नाथन बनाम ट्रम्प के नाम से जाना जा रहा है। ट्रंप ने 6 अगस्त को एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया था। इसका मकसद अमेरिका में पैदा होने वाले कुछ बच्चों को जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता से बाहर रखना था। इससे पहले जून में सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के नागरिकता से जुड़े पुराने आदेश पर रोक लगा चुका था। इसके बाद प्रशासन ने नए आदेश के जरिए कुछ और श्रेणियों के बच्चों को नागरिकता के दायरे से बाहर करने की कोशिश की।

ट्रंप के नए आदेश में उन बच्चों को निशाना बनाया गया था, जिनके माता-पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक नहीं है। इसमें कुछ खास श्रेणियां शामिल थीं। मसलन, ऐसे माता-पिता जिन्हें प्रशासन ने 'दुश्मन देश का विदेशी नागरिक' माना है, विदेशी सरकारों के कर्मचारी और वे लोग जो अमेरिका में बच्चे को जन्म देकर नागरिकता हासिल करने की योजना बनाते हैं। इस आदेश में उन परिवारों को भी शामिल किया गया था, जो पैसे देकर सरोगेसी के जरिए अमेरिका में बच्चे को जन्म दिलवाते हैं। यानी व्यावसायिक सरोगेसी के मामलों में पैदा हुए बच्चों की नागरिकता पर भी सवाल खड़ा किया गया था।

नए आदेश का दायरा सिर्फ विदेशी राजदूतों तक सीमित नहीं था। इसमें दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में काम करने वाले कुछ अन्य कर्मचारियों को भी शामिल किया गया था। ऐसे कर्मचारी, जो अपनी सरकारी जिम्मेदारी निभाने के लिए अमेरिका में रह रहे हैं, उनके बच्चों को भी इस आदेश के तहत नागरिकता से वंचित करने की कोशिश की गई थी। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि इन श्रेणियों के लोग अमेरिकी संविधान के तहत मिलने वाले जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार के दायरे में नहीं आते। अदालत ने प्रशासन की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों के लिए अपनी तरफ से नागरिकता के नए अपवाद नहीं बना सकते।ष्टरु के मुताबिक, अदालत ने माना कि अमेरिकी कानून के तहत आने वाले बच्चों को केवल उनके माता-पिता की नागरिकता या स्थिति के आधार पर जन्मसिद्ध नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता।

अंतरिक्ष में बनेंगे एआई के डेटा सेंटर: स्पेसएक्स को 10 लाख उपग्रह छोड़ने की मंजूरी; जानें कब से होगी तैनाती?

टेक्सास, एजेंसी। अंतरिक्ष में अब सिर्फ इंसान और उपग्रह ही नहीं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बड़े-बड़े डेटा सेंटर भी नजर आएंगे। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (एफसीसी) ने अंतरिक्ष में 10 लाख तक उपग्रह तैनात करने की मंजूरी दी है। इन उपग्रहों की मदद से अंतरिक्ष में ही डेटा सेंटर बनाए जाएंगे, जहां एआई से जुड़े जटिल काम किए जा सकेंगे। इस परियोजना का नाम 'स्टारमाइंड' रखा गया है। इसका मकसद तेजी से बढ़ती एआई की जरूरतों को पूरा करना है।

सूरज की रोशनी से चलेंगे अंतरिक्ष के डेटा सेंटर : इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रह सूरज की रोशनी से ऊर्जा हासिल करेंगे। इसी बिजली से उनमें लगे कंप्यूटर और एआई सिस्टम काम करेंगे। इन उपग्रहों पर बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण किया जाएगा और फिर जरूरी जानकारी धरती पर भेजी जाएगी। इससे जमीन पर बड़े-बड़े डेटा सेंटर बनाने की जरूरत कुछ हद तक कम हो सकती है। साथ ही बिजली और ठंडा रखने पर होने वाला खर्च भी घटने की उम्मीद है।

एफसीसी के अध्यक्ष ब्रेंडन कार ने इस फैसले को अमेरिका के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उनका कहना है कि अमेरिका सुपर इंटेलिजेंस यानी अति विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में दुनिया की अगुवाई कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में देश इस तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में कंप्यूटिंग की क्षमता विकसित करने से निवेश बढ़ेगा, नई संभावनाएं पैदा होंगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। कार के मुताबिक, एआई के क्षेत्र में दुनिया में आगे बने रहने के लिए बड़े डेटा सेंटर बेहद जरूरी हैं। अंतरिक्ष में कंप्यूटिंग की व्यवस्था तैयार होने से अमेरिका को अपनी अंतरिक्ष और आधुनिक तकनीक की ताकत का एक साथ इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। एफसीसी की मंजूरी में उपग्रहों के बीच संपर्क और उन्हें नियंत्रित करने की व्यवस्था भी शामिल है।

ब्रिटेन: ऑक्सफोर्ड में भारतीय छात्रा से नस्लभेद, महिला बोली- 'तुमसे बदबू आती है'

ऑक्सफोर्ड, एजेंसी। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक भारतीय पीएचडी छात्रा ने नस्लभेद को लेकर अपनी आपबीती सुनाई है। उनका नाम कामाक्षी है। उन्होंने शहर में खरीदारी के दौरान अपने साथ हुई एक घटना के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने बड़े शिक्षण संस्थानों में नस्लभेद को लेकर भी अपनी बात रखी। कामाक्षी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। इसमें उन्होंने बताया कि ऑक्सफोर्ड में अलग-अलग रंग और नस्ल के लोगों को किस तरह के बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने यह बात पहले की एक पोस्ट पर नस्लभेदी टिप्पणी आने के बाद कही। उस टिप्पणी के बाद कई लोगों ने उनका समर्थन किया था। उन्होंने कहा, 'आप सभी मेरी तरफ से इतने नाराज थे। इससे मुझे एहसास हुआ कि ऑक्सफोर्ड

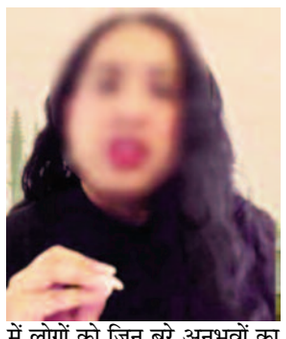

में लोगों को जिन बुरे अनुभवों का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में आपसे बात न करके मैं आपके साथ सही नहीं कर रही थी'।

दुकान में महिला ने क्या कह दिया : कामाक्षी ने अपने साथ हुई एक खास घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह एक स्थानीय दुकान में सामान देख रही थीं। तभी एक श्वेत महिला उनके आसपास चक्कर लगाने लगी। इससे वह काफी असहज हो गईं। कुछ देर बाद वह महिला उनके पास आई। उन पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। कामाक्षी ने बताया, 'बाद में वह मेरे पास आई और उसने कहा। मैं उसके शब्द दोहरा रही हूं, 'मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। तुमसे बहुत, बहुत बदबू आती है'।

इस बात से कामाक्षी हैरान रह गईं। उन्होंने कहा कि वह महिला की बात का जवाब भी नहीं दे पाई। महिला वहां से चली गई। उन्होंने कहा, 'मैं पूरी तरह हैरत में पड़ गई थी। जब तक मेरा दिमाग समझ पाता कि आखिर हुआ क्या है, तब तक वह जा चुकी थी'।

पिता के इत्र से जुड़ी थी यह बात : कामाक्षी ने बताया कि इस टिप्पणी से उन्हें खास तौर पर दुख पहुंचा। इसकी वजह उनके इत्र से जुड़ी एक निजी भावना थी। वह जिस इत्र का इस्तेमाल करती हैं, वही उनके पिता भी लगाते हैं। इस जुड़ाव से उन्हें सुकून मिलने के बजाय इस घटना ने उन्हें दुखी और परेशान कर दिया। उन्होंने बताया कि पूरे दिन वह खुद को कमतर दिखाने की कोशिश करती रहीं। वह नहीं चाहती थीं कि किसी का ध्यान उनकी तरफ जाए। कामाक्षी ने साफ किया कि दुकान में हुई यह घटना कोई अकेली घटना नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। इसमें रोजमर्रा के व्यवहार में होने वाली दुश्मनी से लेकर बड़े संस्थानों की नाकामी तक शामिल है। उन्होंने कहा, 'यह कोई अकेली घटना नहीं है। सड़कों पर छोटी-छोटी नस्लभेदी घटनाओं से लेकर संस्थान की ओर से नस्लवादियों को मंच देने तक, यह सच्चाई है कि कोई भी प्रतिष्ठित संस्थान नस्लभेदी, साम्राज्यवादी या फिर समस्याग्रस्त जड़ों से पूरी तरह मुक्त नहीं है।

अमेरिका में थैंक्सगिविंग पर तूफान का साया: न्यूयॉर्क में तेज बारिश और हवाओं का अलर्ट, न्यू जर्सी में आपातकाल

न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिका में थैंक्सगिविंग से पहले भीषण तूफानों ने छुट्टियों के जश्न और यात्रा की तैयारियों पर असर डालना शुरू कर दिया है। खराब मौसम के पूर्वानुमान के चलते न्यूयॉर्क की मशहूर मैसीज थैंक्सगिविंग डे परेड को शनिवार तक के लिए टाल दिया गया है। वहीं, फिलाडेल्फिया में आयोजकों ने मौसम संबंधी चिंताओं के कारण परेड में गुब्बारे नहीं उड़ाने का फैसला किया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क की मैसीज परेड शनिवार सुबह 8:30 बजे (अमेरिकी पूर्वी समय) शुरू होगी। यह फैसला भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए लिया गया है। दोनों तटों पर तूफान का असर थैंक्सगिविंग की छुट्टियों के दौरान



अमेरिका में आठ करोड़ से ज्यादा लोगों के यात्रा करने की उम्मीद है। ऐसे में पूर्वी और पश्चिमी तट पर खराब मौसम से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूर्वी तट पर सुपरस्टॉर्म सैंडी के बाद सबसे ऊंचे जलस्तर की आशंका जताई गई है। डेलावेयर और न्यू जर्सी के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा है। पश्चिमी तट पर भी तटीय इलाकों में बाढ़ की आशंका बनी हुई है। सैन फ्रांसिस्को के दक्षिण में पैसिफिका इलाके में तेज लहरों के कारण एक पियर का हिस्सा ढह गया। वहीं, सैन डिएगो के आसपास ऊंचे ज्वार के कारण जलस्तर के पुराने रिकॉर्ड टूट गए।

खराब मौसम को देखते हुए एयरलाइंस ने भी यात्रियों को संभावित परेशानी के लिए आगाह किया है। साउथवेस्ट एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस ने थैंक्सगिविंग के दिन पूर्वोत्तर अमेरिका में उड़ानों के प्रभावित होने की आशंका जताई है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकुल ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाओं और तटीय इलाकों में बाढ़ की चेतावनी दी है। उन्होंने लोगों से स्थानीय मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखने और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल ने भी बड़े तूफान की आशंका को देखते हुए पूरे राज्य में आपातकाल घोषित किया है। तूफान के कारण तेज और नुकसान पहुंचाने वाली हवाएं, भारी बारिश, तटीय इलाकों में बाढ़ और लंबे समय तक बिजली गुल रहने की आशंका है। यह आपातकालीन घोषणा बुधवार शाम छह बजे (अमेरिकी पूर्वी समय) से प्रभावी हुई। गवर्नर शेरिल ने छुट्टियों में यात्रा करने वाले लोगों से अपील की कि वे तूफान के सबसे खराब असर से बचने के लिए बुधवार को ही अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करें।

बांग्लादेश- अवामी लीग ने 2 दिन बंद का ऐलान किया



ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी से पहले राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। उनकी पार्टी अवामी लीग ने 27 और 28 नवंबर को देशभर में दो दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। हसीना की पार्टी अवामी लीग ने अपने लॉकडाउन के पीछे 8 मांगें रखी हैं। इनमें पार्टी पर लगा प्रतिबंध हटाना और राजनीतिक बंदियों को रिहा करना शामिल है। वहीं, सरकार ने हसीना की वापसी और बढ़ती हिंसा को देखते हुए सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ा दी है। इस बीच, सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में देशभर में आगजनी की करीब 100 घटनाएं दर्ज की गई हैं।

सीमा पर बॉर्डर सेना की 108 टुकड़ियां तैनात : हसीना की वापसी से पहले तारिक रहमान सरकार ने सीमा से लगे सात जिलों में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 108 टुकड़ियां तैनात की हैं। सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन, बॉडी कैमरों और दूसरे निगरानी उपकरणों की मदद से नजर रख रही हैं। पुलिस ने भी सीमा से लगे इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। जगह-जगह जांच चौकियां बनाई गई हैं और संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा, सीमा से लगे 30 जिलों में प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसियों को संवेदनशील रास्तों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

15 दिन में ग्रामीण बैंक की 100 शाखाओं पर हमला : बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया रहे मुहम्मद यूनुस की ओर से बनाए गए ग्रामीण बैंक की शाखाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। बैंक की 24 नवंबर की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक, 10 नवंबर से अब तक देशभर में इसकी करीब 100 शाखाओं पर हमले हो चुके हैं। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि अवामी लीग को कभी राजनीति नहीं करने दी जाएगी। पार्टी पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कहने-सुनने के समझौते के तहत नई दिल्ली से बातचीत जारी है। हसीना की सत्ता जाने के बाद से सरकार पर विरोध की आवाज दबाने के आरोप लग रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2024 से अक्टूबर 2026 के बीच पत्रकारों को गिरफ्तारी, हिंसा, मुकदमों और आर्थिक रोक का सामना करना पड़ा।

किम जोंग उन ने किया परमाणु ठिकानों का दौरा, सामरिक हथियारों के व्यापक इस्तेमाल पर रहा जोर

सोल, एजेंसी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने बुधवार को देश के परमाणु ठिकानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परमाणु हथियार उत्पादन क्षमता को और मजबूत करने का आह्वान किया। परमाणु सामग्री उत्पादन केंद्रों और हथियार अनुसंधान संस्थान का निरीक्षण करते हुए उन ने कहा कि देश को अलग-अलग सैन्य अभियानों में सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप के अनुसार, किम ने बुधवार को इन परमाणु ठिकानों का दौरा किया। हालांकि, उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए ने अपनी रिपोर्ट में इन केंद्रों के नाम और उनके स्थान का खुलासा नहीं किया। निरीक्षण के दौरान किम ने कहा कि उत्तर कोरिया अपनी परमाणु सामग्री उत्पादन क्षमता का व्यवस्थित और लगातार विस्तार कर रहा है, ताकि देश के परमाणु हथियारों के जखीरे को मजबूत और आधुनिक बनाया जा सके। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों और अलग-अलग सैन्य अभियानों में सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की क्षमता विकसित करने को महत्वपूर्ण और तत्काल आवश्यकता बताया।

किम ने इसके पीछे आधुनिक युद्ध में सामरिक परमाणु हथियारों



की सैन्य उपयोगिता और उत्तर कोरिया की उस देश के साथ साझा सीमा का हवाला दिया, जिसे उन्होंने सबसे खतरनाक शत्रु देश बताया। उनका इशारा दक्षिण कोरिया की ओर था। उत्तर कोरियाई नेता ने अमेरिका पर पूर्वोत्तर एशिया में परमाणु प्रसार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा,' अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ परमाणु हथियार साझा करने और उनके संयुक्त इस्तेमाल की व्यवस्था विकसित कर रहा है। इससे क्षेत्र में एक वैश्विक परमाणु सैन्य गठबंधन प्रणाली तैयार हो रही है। किम ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों में उत्तर कोरिया के लिए अपने परमाणु हथियारों के भंडार को बढ़ाना और भी जरूरी हो गया है। उन्होंने दोहराया कि उत्तर कोरिया की परमाणु शक्ति संपन्न देश की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है और बाहरी देशों के बयानों या परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उत्तर कोरिया ने वर्ष 2023 में अपने संविधान में खुद को परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में स्थापित किया था। किम ने कहा कि परमाणु हथियारों का स्वामित्व देश की संप्रभुता और सुरक्षा की बुनियादी गारंटी है। इसे खत्म करने की किसी भी कोशिश को उत्तर कोरिया अपनी संप्रभुता पर हमला और युद्ध की घोषणा के रूप में देखेगा। इस साल फरवरी में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की नौवीं कांग्रेस में भी उत्तर कोरिया ने अपनी परमाणु हथियार संपन्न देश की स्थिति को अपरिवर्तनीय बताया था।

उस दौरान प्योंगयांग ने पांच वर्षीय सैन्य आधुनिकीकरण योजना के तहत परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने का संकल्प लिया था। यह किम जोंग उन का किसी परमाणु केंद्र का चौथा ऐसा दौरा है, जिसकी जानकारी सरकारी मीडिया ने सार्वजनिक की है। इससे पहले उन्होंने सितंबर 2024, जनवरी 2025 और जून 2026 में भी परमाणु प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था।



टमाटर की खेती

भारत में मटर 7.9 लाख हेक्टेयर भूमि में उगाई जाती है। इसका वार्षिक उत्पादन 8.3 लाख टन एवं उत्पादकता 1029 किग्रा./हेक्टेयर है। मटर उगाने वाले प्रदेशों में उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं। उत्तरप्रदेश में 4.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मटर उगाई जाती है, जो कुल राष्ट्रीय क्षेत्र का 53.7% है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 2.7 लाख हे., उड़ीसा में 0.48 लाख., बिहार में 0.28 लाख हे. क्षेत्र में मटर उगाई जाती है।



उत्पादन तकनीक

भूमि की तैयारी – मटर की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, फिर भी गंगा के मैदानी भागों की गहरी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी रहती है। मटर के लिए भूमि को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। खरीफ की फसल की कटाई के बाद भूमि की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल करके 2–3 बार हैरो चलाकर अथवा जुताई करके पाटा लगाकर भूमि तैयार करनी चाहिए। धान के खेतों में मिट्टी के ढेलों को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे अंकुरण के लिए मिट्टी में नमी होना जरुरी है।

फसल पद्धति– सामान्यतः मटर की फसल, खरीफ ज्वार, बाजरा, मक्का, धान और कपास के बाद उगाई जाती है। मटर, गेंहूँ और जौ के साथ अंत: पसल के रूप में भी बोई जाती है। हरे चारे के रूप में जई और सरसों के साथ इसे बोया जाता है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल में इसकी उतेरा विधि से बुआई की जाती है।

बीजोपचार – उचित राजोबियम संवर्धक (कल्चर) से बीजों को उपचारित करना उत्पादन बढ़ाने का सबसे सरल साधन है। दलहनी फसलों में वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने की क्षमता जड़ों में स्थित ग्रंथिकाओं की संख्या पर निर्भर करती है और यह भी राइजोबियम की संख्या पर भी निर्भर करता है। इसलिए इन जीवाणुओं का मिट्टी में होना जरुरी है। क्योंकि मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए राईजोबियम संवर्धक से बीजों को उपचारित करना जरूरी है।



राईजोबियम से बीजों को उपचारित करने के लिए उपयुक्त कल्चर का एक पैकेट (250 ग्राम) 10 किग्रा. बीज के लिए पर्याप्त होता ही। बीजों को उपचारित करने के लिए 50 ग्राम गुड़ और 2 ग्राम गोंद को एक लीटर पानी में घोल कर गर्म करके मिश्रण तैयार करना चाहिए। सामान्य तापमान पर उसे ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद उसमें एक पैकेट कल्चर डालें और अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण में बीजों को डालकर अच्छी तरह से मिलाएं, जिससे बीज के चारों तरफ इसकी लेप लग जाए। बीजों को छाया में सुखाएं और फिर बोयें। क्योंकि राइजोबियम फसल विशेष के लिए ही होता है, इसलिए मटर के लिए संस्तुत राईजोबियम का ही प्रयोग करना चाहिए। कवकनाशी जैसे केप्टान, थीरम आदि भी राईजोबियम कल्चर के अनुकूल होते हैं। राइजोबियम से उपचारित करने के 4–5 दिन पहले कवकनाशियों से बीजों का शोधन कर लेना चाहिए।

बुआई के समय– मटर की बुआई मध्य अक्तूबर से नवम्बर तक की जाती है जो खरीफ की फसल की कटाई पर निर्भर करती है। फिर भी बुआई का उपयुक्त समय अक्तूबर के आखिरी सप्ताह से नवम्बर का प्रथम सप्ताह है।

बीज–दर, दूरी और बुआई– बीजों के आकार और बुआई के समय के अनुसार बीज दर अलग–अलग हो सकती है। समय पर बुआई के लिए 70–80 किग्रा. बीज/हे. पर्याप्त होता है। पछेती बुआई में 90 किग्रा./हे.बीज होना चाहिए। देशी हल जिसमें पोरा लगा हो या सीड ड्रिल से 30 सेंमी. की दूरी पर बुआई करनी चाहिए। बीज की गहराई 5–7 सेंमी. रखनी चाहिये जो मिट्टी की नमी पर निर्भर करती है। बौनी मटर के लिए बीज दर 100 किलोग्राम/हे. उपयुक्त है।

उर्वरक – मटर में सामान्यत: 20 किग्रा, नाइट्रोजन एवं 60 किग्रा. फास्फोरस बुआई के समय देना पर्याप्त होता है। इसके लिए 100–125 किग्रा. डाईअमोनियम फास्फेट (डी, ए,पी) प्रति हेक्टेयर दिया जा सकता है। पोटेशियम की कमी वाले क्षेत्रों में 20 कि.ग्रा. पोटाश (म्यूरेट ऑफ़ पोटाश के माध्यम से) दिया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में गंधक की कमी हो वहाँ बुआई के समय गंधक भी देना चाहिए। यह उचित होगा कि उर्वरक देने से पहले मिट्टी की जांच करा लें और कमी होने पर उपयुक्त पोषक तत्वों को खेत में दें।

सिंचाई– प्रारंभ में मिट्टी में नमी और शीत ऋतु की वर्षा के आधार पर 1–2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी सिंचाई फलियाँ बनने के समय करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हल्की सिंचाई करें और फसल में पानी ठहरा न रहे।

खतपतवार नियंत्रण – खरपतवार फसल के निमित पोषक तत्वों व जल को ग्रहण का फसल को कमजोर करते हैं और उपज के भारी हानि पहुंचाते हैं। फसल को बढ़वार की शुरू की अवस्था में खरपतवारों से अधिक हानि होती है। अगर इस दौरान खरपतवार खेत से नहीं निकाले गये तो फसल की उत्पादकता बुरी तरह से प्रभावित होती है। यदि खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जैसे–बथुआ, सेंजी, कृष्णनील, सतपती अधिक हों तो 4–5 लीटर स्टाम्प–30 (पैंडीमिथेलिन) 600–800 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर देना चाहिए। इससे काफी हद तक खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है।

रोग एवं कीट प्रबन्धन

रोग

रतुआ – इस रोग के कारण जमीन के ऊपर के पौधे के सभी अंगों पर हल्के से चमकदार पीले (हल्दी के रंग के) फफोले नजर आते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर ये ज्यादा होते हैं। कई रोगी पत्तियाँ मुरझा कर गिर जाती है। अंत में पौधा सुखकर मर जाता है। रोग के प्रकोप से सें संकुचित व छोटे हो जाते हैं। अगेती फसल बोने से रोग का असर कम होता है। अवरोधी प्रजाति मालवीय मटर 15 प्रयोग करें।

आर्द्रजड़ गलन– इस रोग से प्रकोपित पौधों की निचली पत्तियाँ हल्के पीले रंग की हो जाती है। पत्तियाँ नीचे की ओर मुड़कर सुखी और पीली पड़ जाती है। तनों और जड़ों पर खुरदरे खुरंट से पड़ जाते हैं। यह रोग जड़–तंत्र सड़ा डालता है। यह रोग मृदा जनित है। रोग की बीजाणु वर्षों तक मिट्टी में जमे रहते हैं। हवा में 25 से 50% की अपेक्षित आर्द्रता और 22 से 32 डिग्री में सेल्सियस दिन का तापमान रोग पनपने में सहायक होता है। रोगग्राही फसल को उसी खेत में हर साल न उगाएँ। बीज का उपचार करने के लिए कार्बेन्ड़ाजिम 1 ग्राम + थीरम 2 ग्राम मात्रा एक किग्रा. बीज में मिलाएं। फसल की अगेती बुआई से बचें तथा सिंचाई हल्की करें।

चांदनी रोग– इस रोग से पौधों पर एक से.मी. व्यास के बड़े–बड़े गोल बादामी और गड्ढे वाले दाग पीजे जाते हैं। इन दागों के चारों ओर गहरे रंग की किनारों भी होती है। तने पर घेरा बनाकर यह रोग पौधे के मार देता है। रोग मुक्त बीज ही बोयें 3 ग्राम थीरम दवा प्रति किग्रा. बीज की दर से मिलाकर बीजोपचार करें।

तुलासिता/रोमिल फफूंद– इस रोग के कारण पत्तियों की ऊपरी सतह एप पीले और ठीक उनके नीचे की सतह पर रुई जैसी फफूंद छा जाती है और रोगग्रस्त पौधों की बढ़वार रुक जाती है। पत्तियाँ समय से पहले ही झड़ जाती है। संक्रमण अधिक होने पर 0.2% मौन्कोजेब अथवा जिनेब का छिड़काव 400–800 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से करनी चाहिए।

पौध/मूल विगलन– जमीन के पास के हिस्से से नये फूटे क्षेत्रों पर इस रोग का प्रकोप होता है। तना बादामी रंग का होकर सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से पौधे मर जाते हैं। 3 ग्रा. थीरम+1 ग्राम कार्बेन्डाजिम प्रति किग्रा. बीज की दर से बीजोपचार करें खेत का जल निकास ठीक रखें। संक्रमित खेती में अगेती बुआई न करें।

कीट



तना मक्खी – ये पूरे देश में पाई जाती है। पत्तियों, डंठलों अरु कोमल तनों में गांठें बनाकर मक्खी उनमें अंडे देती है। अंडों देती है। अंडों से निकली सड़ी पत्ती के डंठल या कोमल तनों मने सुरंग बनाकर अंदर–अंदर खाती है, जिससे नये पौधे कमजोर होकर झुक जाते हैं और पत्तियों पीली पड़ जाती है। पौधों की बढ़वार रुक जाती है। अंतत: पौधे मर जाते हैं।

मांहू (एफिड) – कभी–कभी मांहू भी मटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इनके बच्चे और वयस्क दोनों ही पौधे का रस चूसने में सक्षम होते हैं। यह रस ही नहीं चूसते, बल्कि जहरीले तत्व भी छोड़ देते हैं। इसका भारी प्रकोप होने पर फलियाँ मुरझा जाती हैं। अधिक प्रकोप होने पर फलियाँ सुख जाती है। मांहू मटर एक वायरस (विषाणु) को फैलाने में भी उसके वाहक बनकर सहायता करती है।

मटर का अधफंदा (सेमीलूपर) – यह मटर का साधारण कीट है। इसकी गिड़ारें पत्तियाँ खाती है। पर कभी–कभी फूल और कोमल फलियों को भी खा जाती हैं। चलते समय यह शरीर के बीचोबीच फंदा सा बनाती है, इसलिए इसका नाम अधफंदा या सेमिलुपर पड़ा। जहाँ पर तना मक्खी या पटसुरंगा या मांहू का प्रकोप हो, वहाँ 2% फोरेट से बीज उपचार करें या 1 किग्रा. फोरेट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की मिट्टी में बुआई के समय मिला दें। आवश्यकता होने पर पहली निकलने की अवस्था में फसल पर 0.03% डामेथोएट 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर घोल कर प्रति हेक्टेयर छिड़कें। जहाँ बुआई के समय मिट्टी में दवा न मिला पाए हों, वहाँ कीट के प्रकोप के अनुसार कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। कटीला फली भेदक (एटीपेला) – यह फली भेदक उत्तर भारत में अधिक पाया जाता है। अगेती किस्म के अपेक्षा पछेती प्रजातियों पर इसका अधिक प्रकोप होता है। इसी तरह देर से बोई गयी फसल में जल्दी बोई गयी फसल की तुलना में अधिक हानि होती है। फली और अंखुबड़ी के जोड़ वाली जगह पर या फली की सतह पर यह पंतगा अंडे देता है। अंडे से निकलते ही इसके नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। कटाई और मड़ाई – मटर की फसल सामन्यत: 130–150 दिनों में पकती है। इसकी कटाई दरांती से करनी चाहिए 5–7 दिन धुप में सुखाने के बाद बैलों से मड़ाई करनी चाहिए। साफ दानों को 3–4 दिन धूप में सुखाकर उनको भंडारण पात्रों (बिन) में करना चाहिये। भंडारण के दौरान कीटों से सुरक्षा के लिए एल्युमिनियम फोस्फाइड का उपयोग करें।

सर्दियों के टमाटर के लिए अभी से करें बिजाई

टमाटर विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली सब्जी है। भारतीय पाक–पकवानों में टमाटर का विशेष महत्व है। इसे सब्जी बनाने से लेकर, सलाद में, सूप के तौर पर, चटनी के रूप में और यहां तक की ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर में विटामिन सी, लाइकोपीन, विटामिन, पोटैशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है. साथ ही इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले तत्व भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। टमाटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि टमाटर को पका देने के बाद भी उसके पोषक तत्व बने रहते हैं। टमाटर की अधिक पैदावार के लिए किसान निम्नलिखित उन्नत तकनीकें अपनाएं।

उन्नत किस्में : हिसार अरुण, हिसार ललित, हिसार लालिमा

बिजाई : टमाटर की मुख्य उपयुक्त किस्में सर्दी के लिए जून से मध्य जुलाई तक बोई जा सकती हैं और वसंत के लिए नवंबर से दिसम्बर तक बोई जा सकती हैं।

बीज की मात्र व बिजाई का तरीका : यदि फसल जून में बो रहे है तो 400–500 ग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से बोये। नवंबर में 200 ग्राम बीज प्रति एकड़ बोयें।

बीज उपचार : बीज जनित रोगों से बचाने के लिए थायिरम या कैप्टान 2.5 ग्राम/किलोग्राम बीज के दर से उपचार करना लाभदायक है।

नर्सरी स्थापना : सर्दी में तैयार होने वाले टमाटर के लिए 3म1 मीटर के 40 बेड प्रति एकड़ और वसंत में होने वाले टमाटर के लिए 15 बेड प्रति एकड़ तैयार करें। गर्मी में लगने वाली पोध 4 हफ्ते और सर्दी में लगने वाली 8–10 हफ्ते में तैयार हो जाती है।

रोपाई : रोपाई का सही समय तब होता है जब पौध में 5–6 पत्तियां निकल आये।

खाद एवं उर्वरक : टमाटर की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खाद एवं उर्वरक का सही मात्रा में प्रयोग अनिवार्य है। बीज की तैयारी करते समय खेत में अंतिम जुताई के बाद 20–25 टन खाद प्रति एकड़ के हिसाब से मिलायें। टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए अंतिम जुताई के समय उसमे 20 किलो पोटाश और 25 किलो फोस्फोरस मिलाए और 40 किलो नाइट्रोजन का तीसरा भाग प्रति एकड़ के हिसाब से मिलायें। बचा हुआ नाइट्रोजन बराबर मात्र में एक चार हफ्ते बाद और एक उसके एक महीने बाद मिलायें।

सिंचाई : पहली सिंचाई रोपाई के बाद दें और उसके बाद हर 8–10 के भीतर सिंचाई करें जब तक टमाटर की फसल तैयार न हो जाये।

निराई गुडाई : टमाटर में खरपतवार का नियंत्रण करना अनिवार्य है यदि आप अच्छी पैदावार चाहते हैं तो नियंत्रण के लिए एक बार 20 से 25 दिन में निराई गुडाई करे और दूसरी 40 से 45 दिन में आवश्यक है।

कटाई का समय : जब टमाटर पर लाल पीली धारियां सी पड़ने लगे तो समझ लीजिये क आपकी फसल तैयार है। यदि टमाटर कही दूर बाज़ार में बेचने हो तो जब वो थोड़े हरे हो तभी उन्हें तोड़ लें।

फल फटने की समस्या और कारण

ठंड के मौसम में टमाटर के फल फटने की समस्या अक्सर होती है, जो उत्पादन में कमी का कारण बनती है। जिला उद्यान अधिकारी डॉ. पुनीत कुमार पाठक के अनुसार, यह समस्या सूखा पड़ने या बोरान की कमी के कारण होती है। इसके अलावा, ऊसर भूमि पर टमाटर की खेती करने से भी यह समस्या बढ़ सकती है।



सर्दी और बारिश से टमाटर की फसल पर असर

खराब मौसम, खासकर सूखा पड़ने के बाद अचानक बारिश होने से टमाटर में फल फटने की समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिए किसानों को सूखा पड़ने पर भी नियमित सिंचाई करनी चाहिए, ताकि बारिश के बाद फल फटने की समस्या कम हो सके।

बोरान की कमी और समाधान

टमाटर में फल फटने की समस्या बोरान की कमी के कारण होती है। इसे रोकने के लिए किसान मिट्टी में 20–25 किलोग्राम बोरान मिला सकते हैं और 0.25% बोरेक्स का घोल टमाटर के पौधों पर छिड़क सकते हैं। इसे 2–3 बार छिड़कने से फल फटने की समस्या रोकी जा सकती है।

ऊसर भूमि पर टमाटर की खेती से बचें

ऊसर भूमि पर टमाटर की खेती से फल फटने की समस्या ज्यादा होती है। इसलिए, किसानों को ऊसर भूमि पर टमाटर की खेती से बचना चाहिए, ताकि वे इस समस्या से बच सकें और बेहतर उत्पादन पा सकें।

उत्तराखंड में पीजी डॉक्टरों के लिए दो साल की सरकारी सेवा अनिवार्य



देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने और पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार, 27 नवंबर 2026 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजकीय मेडिकल कॉलेजों से पीजी (स्नातकोत्तर) चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले डॉक्टरों के लिए दो वर्ष की अनिवार्य सरकारी सेवा बॉन्ड व्यवस्था को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट के इस निर्णय के तहत प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एमडी, एमएस एवं अन्य पीजी पाठ्यक्रम पूरा करने वाले चिकित्सकों को पढ़ाई पूरी होने के बाद दो साल तक सरकारी सेवाएं देनी होंगी। इसमें एक वर्ष राजकीय मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में तथा एक वर्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रदेश के दुर्गम एवं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में सेवाएं देना अनिवार्य होगा।

बॉन्ड तोड़ने पर 60 से 75 लाख रुपये तक की पेनल्टी

सरकार ने इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए बॉन्ड की शर्तें भी निर्धारित की हैं। यदि कोई चिकित्सक निर्धारित अवधि की सरकारी सेवा पूरी किए बिना बॉन्ड तोड़ता है, तो उसे 60 लाख से 75 लाख रुपये तक की पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। यह व्यवस्था वर्तमान शैक्षणिक सत्र से लागू की जाएगी।

पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी होगी दूर

उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी स्वास्थ्य सेवाओं के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद रिक्त होने के कारण स्थानीय लोगों को उपचार के लिए देहरादून सहित अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है।

सरकार का मानना है कि पीजी डॉक्टरों के लिए अनिवार्य सेवा बॉन्ड लागू होने से पहाड़ी क्षेत्रों के अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और आम जनता को अपने नजदीकी सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

अब पीजी में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों पर लागू होगी व्यवस्था

स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडेय के अनुसार, प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रमों में स्टेट और सेंट्रल कोटे के माध्यम से प्रवेश दिए जाते हैं। अभी तक पीजी की पढ़ाई के लिए सरकारी सेवा बॉन्ड की व्यवस्था वैकल्पिक थी। इसके अलावा राज्य कोटे के बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए भी सरकारी सेवा की अनिवार्यता नहीं थी। इसके चलते दूसरे राज्यों से पीजी की पढ़ाई करने उत्तराखंड आने वाले कई चिकित्सक पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अपने राज्यों में लौट जाते थे। इससे प्रदेश को प्रशिक्षित विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता था।

नई व्यवस्था के तहत अब राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से दो वर्ष की सरकारी सेवा का बॉन्ड भरना होगा।

एमबीबीएस के बाद अब पीजी डॉक्टरों के लिए भी अनिवार्य सेवा

उत्तराखंड में पहले से ही राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकारी सेवा बॉन्ड की व्यवस्था लागू है। इसके तहत बॉन्ड के माध्यम से एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थियों को तीन वर्ष तक सरकारी सेवाएं देनी होती हैं। इसके बदले उन्हें लगभग 40 हजार रुपये वार्षिक ट्यूशन फीस देनी होती है।

वहीं, बिना बॉन्ड के एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थियों के लिए वार्षिक ट्यूशन फीस लगभग चार लाख रुपये निर्धारित है। अब इसी तर्ज पर पीजी चिकित्सा शिक्षा में भी सरकारी सेवा बॉन्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और विशेष रूप से जौनसार-बावर सहित दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

हाईटेंशन लाइन से बढ़ी फफराण गांव की समस्या

नई टिहरी। पावर ग्रिड की हाईटेंशन लाइनों से घिरे फफराण गांव की समस्याओं का निराकरण करने के लिए पावर ग्रिड को 15 दिन का समय दिया गया है। एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 400/800 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइनों से ग्रामीणों को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो उन्हें के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में फफराण गांव के प्रधान मुकेश चौहान ने बताया कि ग्राम पंचायत मणगांव का फफराणगांव पावर ग्रिड की हाईटेंशन लाइनों से चारों ओर से घिरा है। इसके चलते ग्रामीण भय और असुरक्षा के माहौल में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत लाइन के कारण उनकी कृषि भूमि चौपट हो गई है वहीं उनके आवासीय भवन भी खतरे की जद में है जिससे ग्रामीण कई सालों के खतरों के साए में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने ग्रामीणों की कृषि भूमि और आवासीय भवनों से संबंधित समस्याओं कर शीघ्र समाधान करने की गुहार लगाई है। एडीएम ने दोनों पक्षों से वार्ता करने के बाद ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए पावर ग्रिड के सीनियर डीजीएम पंकज कुमार को निर्देश दिए कि 15 दिनों के भीतर ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रभावित कृषि भूमि और भवनों का आकलन तैयार कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उत्तराखंड में नौकरशाही के दो बड़े फेरबदल

देहरादून। उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक और वन विभाग में दो महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए नौकरशाही में अहम बदलाव किए हैं। शासन ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी वापस लेकर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम को सौंप दी है। वहीं, भारतीय वन सेवा (कार) के वरिष्ठ अधिकारी बीके गांगटे को अपर प्रमुख वन संरक्षक से पदोन्नत कर प्रमुख वन संरक्षक (बनाया गया है।

शासन के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

आर. मीनाक्षी सुंदरम संभालेंगे ऊर्जा निगमों की कमान

शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ऊर्जा विभाग से जुड़े तीनों प्रमुख निगमों के बोर्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। इनमें उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड शामिल हैं। इससे पहले ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष पद का दायित्व मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन के पास था। मुख्य सचिव बनने के बाद वह इस जिम्मेदारी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाल रहे थे। अब शासन ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आर. मीनाक्षी सुंदरम को सौंप दी है।

बीके गांगटे को प्रमुख वन संरक्षक पद पर पदोन्नति

वहीं, उत्तराखंड वन विभाग के वरिष्ठ भारतीय वन सेवा अधिकारी बीके गांगटे को भी बड़ी प्रशासनिक सौगात मिली है। लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे बीके गांगटे को अपर प्रमुख वन संरक्षक से प्रमुख वन संरक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है।

26 नवंबर 2026 को जारी शासनादेश के अनुसार, उन्हें वेतन मैट्रिक्स लेवल-16 में पदोन्नति प्रदान की गई है। इस पद का वेतनमान 2,05,400 रुपये से 2,24,400 रुपये निर्धारित है।यह पदोन्नति 15 सितंबर 2026 को जारी शासनादेश के तहत सृजित अस्थायी पद के सापेक्ष दी गई है। शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति के बाद बीके गांगटे की तैनाती के संबंध में अलग से आदेश जारी किया जाएगा।

अंकिता हत्याकांड: मेडिकल जांच में अनफिट मिले पूर्व विधायक सुरेश राठौर

देहरादून/हरिद्वार। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी विवाद में पूर्व विधायक सुरेश राठौर को बड़ा झटका लगा है। गुजरात के गांधीनगर में पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले कराई गई मेडिकल जांच में उन्हें अनफिट घोषित कर दिया गया है। इसके चलते फिलहाल उनका पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो सकेगा। बताया जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सुरेश राठौर गांधीनगर से हरिद्वार लौट रहे हैं।

सिर की पुरानी चोट के चलते मेडिकल जांच में अनफिट

सुरेश राठौर के बेटे लक्की राठौर के अनुसार, गुरुवार को आई मेडिकल रिपोर्ट में उनके पिता को टेस्ट के लिए अनफिट बताया गया है। इसकी वजह कई साल पहले हुआ एक सड़क हादसा बताया गया है। हादसे में उनके सिर पर चोट लगी थी, जिसके पुराने निशान मेडिकल जांच के दौरान सामने आए हैं।

जानकारी के मुताबिक, सुरेश राठौर 23 नवंबर को हरिद्वार से गांधीनगर के लिए रवाना हुए थे और पिछले तीन-चार दिनों से वहीं मौजूद थे। अंकिता हत्याकांड से जुड़े कथित ऑडियो और उसमें वीआईपी के जिक्र को लेकर चल रही जांच के सिलसिले में उनके और अभिनेत्री उर्मिला सनावर के टेस्ट की प्रक्रिया चर्चा में थी।



कथित ऑडियो में वीआईपी के जिक्र से गरमाया विवाद

अंकिता भंडारी हत्याकांड करीब तीन साल बाद दिसंबर 2025 में एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया, जब पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बीच बातचीत के कथित ऑडियो-वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए।

इन रिकॉर्डिंग में अंकिता हत्याकांड से संबंधित बातचीत और एक कथित वीआईपी का जिक्र होने के दावे किए गए। वायरल सामग्री में उत्तराखंड भाजपा के पूर्व प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार के नाम कथित वीआईपी के रूप में सामने आने के दावे भी किए गए। हालांकि, इन दावों की सत्यता और संबंधित लोगों की भूमिका जांच का विषय है। मामले में अंकिता के पिता ने भी कथित वीआईपी की पहचान सार्वजनिक करने और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई थी। वहीं, दुष्यंत कुमार गौतम ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए इसे उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि खराब करने की साजिश बताया।

दुष्यंत कुमार गौतम ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी

कथित ऑडियो-वीडियो विवाद के बीच जनवरी 2026 में दुष्यंत कुमार गौतम ने सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ देहरादून के डालनवाला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनके खिलाफ भ्रामक ऑडियो-वीडियो तैयार कर प्रसारित किए गए हैं।

इसके बाद गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि याचिका भी दायर की थी। जनवरी 2026 में अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य सोशल मीडिया हैंडल को संबंधित आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिए थे।

संक्षिप्त समाचार

ठेकेदार, अधिकारियों की लापरवाही से गर्जिया मंदिर के टीले पर खतरा

नैनीताल। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर के टीले को बाढ़ और कटाव से बचाने के लिए चल रहे सुरक्षात्मक निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही सामने आई है। ठेकेदार और संबंधित विभागीय अधिकारियों की मनमानी व सुरक्षा मानकों की अनदेखी से न केवल निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं, बल्कि मंदिर के टीले पर ही खतरा मंडराने लगा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता संजय शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए ठेकेदार व अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण तलब किया है तथा नोटिस भेजने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोसी नदी के किनारे स्थित लगभग 70 फीट ऊंचे टीले पर विराजमान माता गर्जिया देवी के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। कोसी नदी में हर साल आने वाली बाढ़ और तेज बहाव के कारण मंदिर का टीला जर्जर और कमजोर होने लगा था। इस स्थिति को देखते हुए शासन ने टीले के संरक्षण और मजबूती के लिए साढ़े 11 करोड़ रुपये की लागत से चारों ओर सीढ़ीनुमा सीसी ब्लॉक (सीमेंट-कंक्रीट ब्लॉक) बनाने की योजना को स्वीकृति दी थी। इसी के तहत सुरक्षात्मक कार्य शुरू किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर नियमों को ताक पर रखकर काम किए जाने से स्थिति चिंताजनक हो गई।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना: 6.59 किमी लंबी टनल-14 का ब्रेकथ्रू

रुद्रप्रयाग। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण कार्य में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) ने 27 नवंबर को रुद्रप्रयाग जिले में 6.59 किलोमीटर लंबी टनल-14 का मुख्य ब्रेकथ्रू पूरा कर लिया। इसके साथ ही सुरंग के दोनों छोर आपस में जुड़ गए हैं। सुरंग की खुदाई पोर्टल-1 सुमेरपुर की ओर से 4.7 किलोमीटर और पोर्टल-2 मरौड़ा की ओर से 1.79 किलोमीटर की गई है। 27 महीने की चुनौतीपूर्ण खुदाई के बाद यह बड़ी सफलता मिली है। आबादी वाले क्षेत्र के नीचे ढीली मिट्टी और पहाड़ी की जटिल भूगर्भीय परिस्थितियों में यहां निर्माण कार्य किया गया है। आरबीएनएल के उपमहाप्रबंधक सिविल ओमप्रकाश मालगुड़ी ने बताया किटनल-14 का निर्माण कई तकनीकी चुनौतियों के बीच किया गया। पोर्टल-1 की ओर आबादी वाले क्षेत्र के नीचे करीब 110 मीटर हिस्से में बेहद ढीली मिट्टी और कम गहराई में पहाड़ की ऊपरी सतह होने के कारण खुदाई चुनौतीपूर्ण थी। उन्होंने बताया कि इस हिस्से में जमीन के ऊपर केवल 20 से 30 मीटर तक मिट्टी और चट्टान की परत थी। ऐसे में आसपास के मकानों और आबादी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष तकनीक से खुदाई की गई। इसके लिए प्री-एक्सकेवेशन और मल्टी-ड्रिफ्टिंग तकनीक अपनाई गई।

77 बैंक शाखाओं में नकली नोट पहचानने की मशीनें स्थापित

चंपावत। भारत-नेपाल सीमा पर आर्थिक अपराधों की रोकथाम और वित्तीय सुरक्षा के लिए जिला सभागार में डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में सीमा संबंधी मुद्दों एवं कार्रवाई समिति (बीआईएसी) की मासिक बैठक हुई।

इसमें नवंबर की सीमा प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की गई। बैठक में बताया कि जिले की बैंक शाखाओं में नकली नोटों की पहचान के लिए अक्तूबर तक 67 मशीनें स्थापित थीं। नवंबर में 10 और मशीनें लगने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 77 हो गई है। जिले में 23 बैंकों की कुल 77 शाखाएं संचालित हैं। इनमें जिला सहकारी बैंक की 10, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की नौ, वाणिज्यिक बैंकों की 57 और लघु वित्त बैंक की एक शाखा शामिल है।

कांग्रेस को अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में दिख रहा है-राम माधव

देहरादून। भारतीय संविधान देश की एकता, अखंडता, समानता और सामाजिक न्याय का मजबूत आधार है। संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों का मार्गदर्शक है। संविधान की मूल भावना को समझते हुए उसे अपने व्यवहार और जीवनशैली में अपनाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यह बात भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव ने संविधान दिवस पर आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कही। 26 नवंबर को भाजपा महानगर देहरादून के अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में दून मेडिकल कॉलेज, देहराखास में सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राम माधव के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्रनाथ शर्मा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना, कैबिनेट मंत्री खजान दास सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्धजन मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। अपने संबोधन में राम माधव ने संविधान निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा और उसके लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डॉ. आंबेडकर के नेतृत्व में निर्मित संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और अवसर प्रदान किए हैं। यह सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला राष्ट्रीय मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई। संविधान किसी राजनीतिक दल का दस्तावेज नहीं, बल्कि पूरे देश का गौरव है। भाजपा संविधान के मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मर्यादाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकारों का दायित्व है कि विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राम माधव ने कहा कि कांग्रेस संविधान की रक्षा को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि संविधान को खतरा नहीं है, बल्कि कांग्रेस को अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संविधान में किए गए बदलावों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान सुरक्षित हाथों में है। राम माधव ने कार्यकर्ताओं से संविधान के अधिकारों के साथ नागरिक कर्तव्यों को भी समझने और आमजन तक सही जानकारी पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों और मूल्यों की जानकारी समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना जरूरी है।

अग्निकांड के बाद जल जीवन मिशन की खुली पोल

पुरोला। मोरी विकासखंड के पवाणी गांव में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जल जीवन मिशन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों का कहना है कि योजना के तहत घरों तक नल कनेक्शन तो पहुंचा दिए गए लेकिन पिछले कई महीनों से पानी की आपूर्ति ठप है। उनका कहना है कि अग्निकांड के दौरान नलों में पानी उपलब्ध होता तो आग बुझाने के शुरुआती प्रयासों में मदद मिल सकती थी और नुकसान कम किया जा सकता था।

गांव के सामाजिक कार्यकर्ता यशपाल सिंह पंवार ने बताया कि पेयजल लाइन बिछाने के साथ अधिकांश घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं लेकिन लंबे समय से पानी नहीं आ रहा है। अग्निकांड के दौरान ग्रामीणों को आग बुझाने के लिए पानी की तलाश में भटकना पड़ा है। पर्याप्त पानी नहीं मिलने से आग तेजी से फैलती चली गई और कई मकान इसकी चपेट में आ गए।

ग्रामीणों ने प्रशासन और जल संस्थान से गांव में नियमित जलापूर्ति बहाल करने की मांग की है। उनका कहना है कि पेयजल व्यवस्था आपदा के समय भी बेहद महत्वपूर्ण है।

वहीं, सहायक अभियंता जल निगम टीएस भंडारी ने बताया कि संबंधित पेयजल योजना पहले ही ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की जा चुकी है। अब इसके संचालन, रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पंचायत को कुछ पीवीसी पाइप भी उपलब्ध कराए गए थे।

स्यांसू-मटियाली सड़क की बदहाली से ग्रामीणों में आक्रोश

कंडीसौड़ (टिहरी)। थौलधार ब्लॉक के पांच राजस्व गांवों को जोड़ने वाली स्यांसू-मटियाली सड़क बदहाली का दंश झेल रही है। आठ किमी लंबी इस सड़क का निर्माण वर्ष 2007 में हुआ था लेकिन करीब 19 साल बीतने के बाद भी इस पर डामरीकरण नहीं हो पाया है। नतीजतन सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बने हैं। उखड़ी सड़क और गड्ढों के बीच ग्रामीणों को जोखिम भरा सफर करना पड़ रहा है।सड़क की हालत इतनी खराब है कि वाहन गुजरते ही धूल के गुबार उठने लगते हैं। इससे सामने और पीछे से आने वाले वाहन स्पष्ट दिखाई नहीं देते। ऐसे में हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। सड़क पर गड्ढे होने से वाहन चालकों को भी आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है। स्यांसू-मटियाली सड़क से मटियाली, चौपड़ा, रतवाड़ी, लाव्खा और मजोली गांवों के सैकड़ों लोग प्रतिदिन जिला मुख्यालय, तहसील और बाजार के लिए आवागमन करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर डामरीकरण और नालियों के निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसके लिए विभिन्न मंचों के साथ ही शासन-प्रशासन को कई बार ज्ञापन भी भेजे गए लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्राम प्रधान मुकेश सिंह जड़धारी, पूर्व प्रधान मधु जड़धारी, जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र रांगड़, ज्ञान चंद रमोला, शंकर चंद रमोला का कहना है कि सड़क की बदहाली से ग्रामीणों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है।

शराबी युवकों का तांडव, सिक्योरिटी गार्ड की चाकू मारकर हत्या

रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवकों को टोकना एक सिक्योरिटी गार्ड को भारी पड़ गया। आरोप है कि युवकों ने विरोध करने पर सिक्योरिटी गार्ड और बीच-बचाव करने आए लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात में सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई, जबकि उसके भांजे समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

ड्यूटी से घर लौटते समय हुआ विवाद

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रुद्रपुर के रमपुरा स्थित रेशमबाड़ी निवासी 50 वर्षीय लीलाधर एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत थे। गुरुवार रात ड्यूटी पूरी करने के बाद वह घर लौट रहे थे। इसी दौरान घर के पास कुछ युवक कथित तौर पर शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि युवकों के हंगामे को देखकर लीलाधर के भांजे राहुल पुत्र विजेंद्र पाल ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। इस बात पर



आरोपी युवक भड़क गए और राहुल के साथ मारपीट शुरू कर दी।

बीच-बचाव करने पहुंचे मामा पर चाकू से हमला

भांजे राहुल के साथ मारपीट होते देख लीलाधर बीच-बचाव करने पहुंचे। आरोप है कि इसी दौरान युवकों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने राहुल के अलावा राम अवतार और अनुज पर भी चाकू से वार किए, जिससे चारों लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने सिक्योरिटी गार्ड लीलाधर को मृत घोषित कर दिया, जबकि राहुल, राम अवतार और अनुज का अस्पताल में उपचार जारी है।

पुलिस ने शुरू की जांच, आरोपियों की तलाश

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। पुलिस द्वारा घायलों से पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

उत्तराखंड में एक साल में 8.46 लाख टन घटा गन्ना उत्पादन

हल्द्वानी। उत्तराखंड में गन्ना उत्पादन, चीनी मिलों की स्थिति और किसानों के बकाया भुगतान को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। प्रदेश में एक वर्ष में लगभग 8.46 लाख टन उत्पादन की कमी दर्ज हुई है। इसी अवधि में गन्ने का कुल क्षेत्रफल 90,364.93 हेक्टेयर से घटकर 88,603.05 हेक्टेयर रह गया है।

आरटीई एक्टविस्ट हेमंत सिंह गोनिया की ओर से मांगी गई सूचनाओं के जवाब में गन्ना विकास विभाग, सहकारी गन्ना विकास समितियों और चीनी मिलों से प्राप्त सरकारी दस्तावेज में राज्य के गन्ना उत्पादन से लेकर किसानों के बकाया तक की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में गन्ने का कुल उत्पादन 75.36 लाख टन था, जो वर्ष 2025-26 में घटकर 66.90 लाख टन रह गया। औसत उत्पादकता भी 834 क्विंटल प्रति



हेक्टेयर से घटकर 755 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई। बकाया भुगतान के मामलों में सबसे गंभीर मामला इकबालपुर चीनी मिल का है। पेराई सत्र 2018-19 का गन्ना मूल्य बकाया लगभग 106.04 करोड़ रुपये है। इस पर 7.50 प्रतिशत दर से ब्याज लगभग 56.19 करोड़ रुपये बनता है। इस तरह कुल बकाया लगभग 162.23 करोड़ रुपये हो गया है।

गन्ने की खेती घटने के विभागीय कारण

विभाग ने गन्ने की खेती घटने के पीछे शहरीकरण का बढ़ता प्रभाव, गन्ने की खेती में श्रमिकों की कमी, चीनी के बाजार भाव में गिरावट, चीनी मिल बंद होने से किसानों का दूसरी फसलें अपनाना आदि कारण बताए हैं। इकबालपुर क्षेत्र में वर्ष 2026-27 के लिए गन्ना उत्पादन में 30.72 प्रतिशत की कमी का अनुमान है।

जयन्त
संस्थापक : नरेन्द्र उनियाल
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस बदरीनाथ मार्ग, कोटद्वार गढ़वाल (उत्तराखण्ड) से मुद्रित तथा बदरीनाथ मार्ग, कोटद्वार गढ़वाल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित।
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र कोटद्वार, (गढ़वाल) उत्तराखण्ड होगा।
CONT. 9412081969
PRGI NO. 35469/79

उत्तर रेलवे
ई-नीलामी
पंजीकृत संस्थाओं से वाणिज्यिक विज्ञापन अनुबंध, किराना सह वाणिज्यिक कियोस्क, प्रीमियम ब्रांड आउटलेट, फूड वैन, सैलून कियोस्क, ग्रोसरी कम कमर्शियल कीओस्क, बैटरी चालित वाहन आदि के अनुबंधों के आवंटन हेतु वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक / कोचिंग, (ए.सी.ओ), मुरादाबाद (ACO) द्वारा दिनांक 11.12.2026 को IREPS के माध्यम से ई-नीलामी हेतु बोलियां आमंत्रित की गई हैं। संबंधित कैटलॉग IREPS की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं। विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। 4140/2026
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

चेस... कोलकाता में जनवरी 2027 में सजेगा ग्रैंडमास्टर शतरंज टूर्नामेंट

नई दिल्ली, एजेंसी। 2018 में शुरू हुए 'टाटा स्टील चेस इंडिया' (जो कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में आयोजित नहीं हो सका था) के रैपिड सेक्शन में मैग्नस कार्लसन और निहाल सरीन दो-दो बार जीत हासिल कर चुके हैं। 'सिटी ऑफ जॉय' कहलाने वाले कोलकाता में एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। 7 से 10 जनवरी 2027 तक यहां एक बड़ा ग्रैंडमास्टर टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसमें कई शीर्ष शतरंज खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। चार दिवसीय टूर्नामेंट में रैपिड और ब्लिट्ज दोनों फॉर्मेट शामिल होंगे। इसका आयोजन कोलकाता के 'धोनो धान्यो ऑडिटोरियम' में किया जाएगा। 'टाटा स्टील चेस इंडिया' दुनिया के शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों को अपना कौशल दिखाने, उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और खेल प्रेमियों को एक शानदार माहौल में जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। शतरंज के साथ कोलकाता के पुराने और गहरे जुड़ाव तथा इस खेल के प्रति यहां बढ़ते उत्साह को देखते हुए, यह इवेंट भारतीय शतरंज कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण आयोजन साबित होगा। 2018 में शुरू हुए 'टाटा स्टील चेस इंडिया' (जो कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में आयोजित नहीं हो सका था) के रैपिड सेक्शन में मैग्नस कार्लसन और निहाल सरीन दो-दो बार जीत हासिल कर चुके हैं।



टेनिस... एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, 70वीं जीत दर्ज की

पेरिस, एजेंसी। ज्वेरेव ने 2024 में 69 मैच जीते थे, लेकिन इस साल उन्होंने उससे भी बेहतर प्रदर्शन किया। 70 जीत का आंकड़ा पार करके उन्होंने अपने करियर का नया व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाया और एक नया बेंचमार्क स्थापित किया। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपने करियर में एक और यादगार अध्याय जोड़ा है। वह इस सदी के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में कम से कम 70 टूर-लेवल जीत दर्ज की हैं।



उन्होंने गुरुवार को बोलोग्ना में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी के डेविस कप फाइनल्स क्वार्टर-फाइनल में आर्थर फेरी पर सीधे सेटों में जीत के साथ यह मुकाम हासिल किया। जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इस उपलब्धि के साथ खुद को पुरुष टेनिस के महान खिलाड़ियों की सूची में शामिल कर लिया है। रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी अपने बेहतरीन सीजन में 70 या उससे अधिक मैच जीत चुके हैं। ज्वेरेव ने 2024 में 69 मैच जीते थे, लेकिन इस साल उन्होंने उससे भी बेहतर प्रदर्शन किया। 70 जीत का आंकड़ा पार करके उन्होंने अपने करियर का नया व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाया और एक नया बेंचमार्क स्थापित किया। 2026 का सीजन अलेक्जेंडर ज्वेरेव के लिए बेहद यादगार रहा।

क्रिकेट... पीसीबी ने किया महिला टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान

लाहौर, एजेंसी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने 2026/27 सीजन के लिए आठ महिला क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है, जिसमें कप्तान फातिमा सना और सीनियर स्पिनर सादिया इकबाल को ए कैटेगरी में रखा गया है। 25 साल की फातिमा को बल्ले और गेंद दोनों से लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए इनाम मिला है। वह हाल ही में इंग्लैंड में 'द हंड्रेड' और ऑस्ट्रेलिया में 'विमेंस बिग बैश' में खेलने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर बनीं। इस बीच, सादिया ने पाकिस्तान की टॉप परफॉर्मर में अपनी जगह बनाए रखी है। बाएं हाथ की स्पिनर पहले आईसीसी टी20 इंटरनेशनल बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर रह चुकी है। मुनीबा अली सिद्दीकी, नशरा संधू और सिदरा अमीन को सभी फॉर्मेट में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन और योगदान के लिए कैटेगरी बी में रखा गया है। गुल फिरोजा और सदफ शमास की ओपनिंग जोड़ी को अनुभवी खिलाड़ी आयशा जफर के साथ कैटेगरी सी में शामिल किया गया है। उनका शामिल होना उनके हाल के घरेलू और इंटरनेशनल प्रदर्शन के साथ-साथ टीम की भविष्य की जरूरतों को दिखाता है। पीसीबी ने एक बयान में कहा, 'कॉन्ट्रैक्ट 30 जून, 2027 तक चलेंगे। खिलाड़ियों की हालिया फॉर्म और फिटनेस को देखते हुए कैटेगरी तय की गई हैं। फिटनेस असेसमेंट रेगुलर किए जाएंगे।



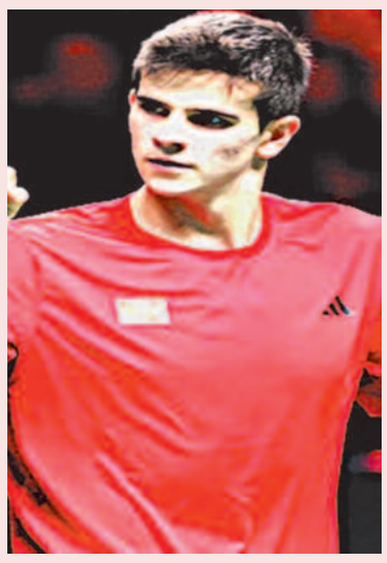

स्पेन ने कटाया डेविस कप के सेमीफाइनल का टिकट, ऑस्ट्रिया को दी शिकस्त

बोलोग्ना (इटली), एजेंसी। स्पेन ने गुरुवार को ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर डेविस कप फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम की जीत की नींव डेनियल मेरिडा ने रखी, जिन्होंने पहला मुकाबला जीतकर स्पेन को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद राफेल जॉडार ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए पिछड़ने के बावजूद वापसी की और अपना मैच जीतकर स्पेन की टाई में जीत सुनिश्चित कर दी। इस जीत के साथ स्पेन ने कुल मिलाकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की और सेमीफाइनल का टिकट कटाया। एटीपी फाइनल्स में अपनी सफलता के बाद मौजूद रहे कार्लोस अल्काराज को कोर्ट पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि स्पेन का शनिवार को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ आखिरी-चार का मुकाबला होना था। मेरिडा ने शुरुआती सिंगल्स मुकाबले में जोएल श्वार्जलर पर 6-4, 6-4 की शांत जीत के साथ स्पेन की जीत की नींव रखी। फिर जॉडार ने यह पक्का किया कि निर्णायक डबल्स मैच की जरूरत न पड़े, और जुरिज रोडियोनोव के खिलाफ 2-6, 6-0, 6-1 से शानदार जीत हासिल की। पहला सेट हारने के बाद 20 साल के खिलाड़ी का जवाब खास तौर पर शानदार था, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए आखिरी 13 में से 12 गेम जीते। उनकी पहली सर्विस की काबिलियत अहम साबित हुई, जिसमें रोडियोनोव के साथ अपनी पहली एटीपी मीटिंग में जॉडार ने अपनी पहली डिलीवरी के बाद 94 प्रतिशत (63/67) पॉइंट जीते।

यूरोपा लीग... बॉर्नमाउथ ने सेल्टा विगो को 2-1 से हराया

नई दिल्ली, एजेंसी। 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही बॉर्नमाउथ ने यूईएफए यूरोपा लीग में सेल्टा विगो को 2-1 से हराया। टीम ने पहले हाफ में पिछड़ने के बावजूद शानदार वापसी की और लगातार पांचवें मुकाबले में जीत दर्ज की। इस जीत के साथ बॉर्नमाउथ का सभी प्रतियोगिताओं में जीत का सिलसिला 10 मैचों तक पहुंच गया है। बॉर्नमाउथ ने पिछड़ने के बाद दमदार वापसी करते हुए मैच अपने नाम किया और यूईएफए प्रतियोगिता के अपने पहले पांच मुकाबले जीतने वाला सिर्फ पांचवां क्लब बन गया है। सेल्टा विगो ने बढ़त तब हासिल की जब अनुभवी फॉरवर्ड इयागो एस्पास ने गोल किया। इससे कुछ देर पहले उनकी शानदार ओवरहेड किक को गोलकीपर मिशेल डि ग्रेगोरियो ने बचा लिया था, लेकिन 39 वर्षीय खिलाड़ी ने बाद में पोस्ट के अंदर की ओर सटीक शॉट लगाकर टीम को बढ़त दिलाई। बाफोडे डायकाइट के बाहर होने से बॉर्नमाउथ को झटका लगा, लेकिन टीम ने दूसरे हाफ की शुरुआत में ही वापसी कर ली। अमीन एडली के शानदार पास पर अल्वारो रोड्रिगेज ने गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद सब्स्टीट्यूट रेयान ने इस अभियान का अपना चौथा गोल दागते हुए बॉर्नमाउथ को बढ़त दिलाई और मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया।

इस जीत के साथ बॉर्नमाउथ ने पांच मैचों में 15 अंक हासिल कर लिए हैं और 36 टीमों की स्टैंडिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। वहीं, सेल्टा विगो की टीम सिर्फ तीन अंकों के साथ 32वें स्थान पर मौजूद है। वहीं, इटली की बड़ी टीमें एसी मिलान और जुवेंटस, दोनों ने मुकाबले में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए अहम जीत हासिल की। ओमारी हचिंसन के शानदार प्रदर्शन ने मिलान को एथेंस में ओलंपियाकोस के खिलाफ 2-0 से पिछड़ने के बाद 4-2 से आगे निकलने में मदद की।



ओलंपियाकोस लीग चरण में अपने अपराजित अभियान को जारी रखने की ओर बढ़ रहा था। पहले हाफ में माइक मेगनन के आत्मघाती गोल और ब्रेक के तुरंत बाद जोआओ सिल्वा के शानदार गोल की बदौलत ग्रीक क्लब ने मजबूत बढ़त बना ली थी। हालांकि, एलेक्स हचिंसन ने अपने ही हाफ से शानदार सोलो रन लगाकर एसी मिलान की वापसी की उम्मीद जगाई। इसके बाद इंग्लिश विंगर ने अल्फाजो सिसे के लिए सटीक क्रॉस दिया, जिस पर बैक पोस्ट पर हेडर से गोल हुआ। फिर क्रिश्चियन पुलिसिक ने भी इसी तरह के मूव पर शानदार वॉली लगाकर स्कोर बराबर कर दिया।स्टॉपेज टाइम में डिएगो मोरेरा ने काउंटर-अटैक पर गोल दागकर एसी मिलान की जीत पक्की कर दी। इस नतीजे के साथ मिलान ने ओलंपियाकोस के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की। इस बीच, एंड्रिया कैम्बियासो के शानदार बराबरी वाले गोल की मदद से जुवेंटस ने ट्यूरिन में ओमोनिया के खिलाफ 4-1 से बड़ी जीत हासिल की। लुबोमिर सतका ने कॉर्नर से ओमोनिया को बढ़त दिलाई, लेकिन कैम्बियासो ने दूर से गोल किया और जेफ एकाटोर ने बॉक्स के अंदर से गोल करके मेजबान टीम को हाफ-टाइम में बढ़त दिला दी।दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए, जुवेंटस ने अपनी बढ़त तब और बढ़ा ली जब फ्रांसिस्को कॉन्सेइकाओ ने थॉमस कामिंस्की के शुरुआती शॉट को बचाने के बाद गोल किया और जेरेमी बोगा के बॉक्स के किनारे से किए गए शानदार फिनिश से चौथा गोल दागा।

यकीन करना मुश्किल है कि फिर सिराज को बाहर कर दिया

मोहम्मद कैफ तेज गेंदबाज को एक बार फिर प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने से नाखुश

नई दिल्ली, एजेंसी। *भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को एक बार फिर प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी गई है। टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर भारत के पूर्व क्रिकेटर्स ने नाराजगी जताई है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ सिराज को एक बार फिर प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने से नाखुश दिखाई दिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'यकीन करना मुश्किल है कि भारत के सबसे अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक मोहम्मद सिराज को फिर से बाहर कर दिया गया है। सिराज को बुमराह के साथ भारत के विदेशी टेस्ट बॉलिंग अटैक में सबसे पहले चुना जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने खुद सिराज को वर्ल्ड-क्लास बॉलर कहा था और बताया था कि वह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं।' वहीं, पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल ने लिखा, 'एक बार फिर मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली।' मुनाफ ने अपने एक और ट्वीट में मौजूदा बॉलिंग अटैक पर भी सवाल खड़े किए।*

उन्होंने लिखा, 'चलो, कोई बात नहीं अगर आप मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपकी अगली बॉलिंग यूनिट कहां है, जो मैच जिताने में माहिर हो? '

क्रिकेट विशेषज्ञ और कमेंटेटर हर्षा भोगले ने अपने एक्स अकाउंट पर सिराज को लेकर लिखा, 'सिराज अब भारत के छठे रैंक वाले तेज गेंदबाज हैं। मुझे यह बहुत गलत लगता है। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में टेस्ट क्रिकेट में टॉप 5 विकेट लेने वालों में भारत के पास अब सिर्फ बुमराह के लिए जगह है। आप चाहते हैं कि बॉलर अच्छे से चुने जाएं, उनके पास बॉलिंग के लिए बेहतरीन कंडीशन हैं, लेकिन उन्हें पता होगा कि जब उनकी बारी आएगी तो उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। '

मोहम्मद सिराज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के मौजूदा साइकिल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वह इस साइकिल में अब तक 43 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। सिराज को इस साल सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला है और इस दौरान उन्होंने 5 विकेट चटकाए हैं। साल 2020 में डेब्यू करने के बाद यह पहला मौका है, जब सिराज किसी विदेशी टेस्ट सीरीज में बिना कोई मैच खेले लौटेंगे।



इंडिया-न्यूजीलैंड टेस्ट

क्राइस्टचर्च टेस्ट में पहला दिन समाप्त....

न्यूजीलैंड का स्कोर 246/5 आकाशदीप की शानदार गेंदबाजी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जा रहा है. मुकाबले में पहले दिन (27 नवंबर) स्टम्प तक न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 246 रन बना लिए. टॉम ब्लंडेल 53 और ग्लेन फिलिप्स 36 रन बनाकर नॉटआउट हैं. भारत की ओर से आकाश दीप ने दो विकेट झटके हैं.

इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम में मोहम्मद सिराज को फिर मौका नहीं मिला. प्रसिद्ध कृष्णा की जगह गुरनूर बरार खेल रहे हैं. बरार का यह पहला टेस्ट मैच है.

पहली पारी में ऐसी रही है न्यूजीलैंड की बैटिंग

न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने पहली पारी में दमदार शुरुआत की. कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे ने पहले विकेट के लिए 77 रनों की पार्टनरशिप की. अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे गुरनूर बरार ने खतरनाक दिख रहे कॉन्वे को 31 रनों के निजी पर आउट कर पवेलियन भेजा. ये विकेट पहले दिन लंच से पहले आखिरी गेंद पर गिरा. लंच के टॉम लैथम ने अपनी फिफ्टी पूरी की. लैथम ने 128 गेंदों पर 59 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल रहे. लैथम का विकेट आकाश दीप ने लिया. फिर अंशुल कम्बोज ने हेनरी निकोल्स (16 रन) को आउट कर भारत को तीसरी कामयाबी दिलाई. 110 के स्कोर पर ही न्यूजीलैंड का एक और विकेट गिरा, जब आकाश दीप के बिछाए जाल में रचिन रवींद्र (0 रन) फंस गए.यहां से टॉम ब्लंडेल और डेरिल मिचेल ने पांचवें विकेट के लिए 74 रन जोड़कर मेजबान टीम को संभाला. मिचेल 31 रनों के निजी स्कोर वॉशिंगटन सुंदर का शिकार बने, जिसके चलते ये साझेदारी टूटी. मिचेल के आउट होने के बाद ग्लेन फिलिप्स ने टॉम ब्लंडेल संग मोर्चा संभाला. दोनों ने छठे विकेट के लिए नाबाद 62 रन जोड़कर न्यूजीलैंड को पहले दिन के खेल में कोई और नुकसान नहीं होने दिया.

33 मैच, 33 अलग मैदान... टेस्ट क्रिकेट में बनाया अनोखा रिकॉर्ड

सचिन से भी आगे निकले यशस्वी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में एक दुर्लभ उपलब्धि अपने नाम की है. यशस्वी अपने शुरुआती 33 टेस्ट मैच अलग-अलग मैदानों पर खेलने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए. उनसे पहले यह कारनामा भारत के संजय मांजरेकर ने किया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में उतरते ही उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया.

यशस्वी जायसवाल ने जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डोमिनिका में टेस्ट डेब्यू किया था. तब से उनके सभी 33 मुकाबले अलग-अलग वेन्यू पर हुए हैं. मांजरेकर ने भी अपने शुरुआती 33 टेस्ट 33 मैदानों पर खेले थे.

यशस्वी ने सचिन को पछाड़ा

यशस्वी जायसवाल महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए हैं. मास्टर ब्लास्टर सचिन ने अपने शुरुआती 32 टेस्ट अलग-अलग मैदानों पर खेले थे. पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ और वेस्टइंडीज के दिनेश रामदीन ने अपने पहले 24-24 टेस्ट अलग-अलग वेन्यू पर खेले थे.यशस्वी जायसवाल ने अब तक सात टीमों के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेला है. इनमें इंग्लैंड के खिलाफ 10, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच-पांच, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ चार-चार, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ दो-दो तथा अफगानिस्तान के खिलाफ एक मुकाबला शामिल है.यशस्वी जायसवाल के पास 2027 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में यह रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा. नागपुर में 21 से 25 जनवरी तक होने वाले मुकाबले में खेलने पर उनका यह सिलसिला 34 मैचों तक पहुंच जाएगा.हालांकि, इसके बाद यह क्रम टूट सकता है. सीरीज के अगले चार टेस्ट चेन्नई, गुवाहाटी, रांची और अहमदाबाद में खेले जाएंगे. यशस्वी जायसवाल इन सभी मैदानों पर पहले ही टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं. ऐसे में नागपुर के बाद चेन्नई में उतरते ही उनका रिकॉर्ड बनाने का सफर थम जाएगा.

जयदेव उनादकट ने टी20 में रचा इतिहास

11वें नंबर पर खेली सबसे बड़ी पारी; 22 साल बाद टूटा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का रिकॉर्ड



नई दिल्ली, एजेंसी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 के 7वें चरण के मैच में एक विश्व कीर्तिमान बना। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना तमिलनाडु और सौराष्ट्र के मुकाबले में। इस मैच में सौराष्ट्र के 11वें नंबर के खिलाड़ी और भारत के लिए खेल चुके जयदेव उनादकट ने इतिहास रच दिया। उन्होंने 11वें नंबर पर आते हुए 26 गेंद पर 40 रनों की पारी खेली। यह टी20 क्रिकेट के इतिहास में 11वें नंबर के बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी रही। आपको बता दें कि उन्होंने 22 साल पुराना ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले टी20 में 11वें नंबर पर सबसे बड़ी नाबाद 24 रन की पारी ऑस्ट्रेलिया में जन्मे एमएफ क्लीरी ने इंग्लैंड के एक घरेलू टी20 मैच में खेली थी। उन्होंने लीसेस्टर के लिए डरहम के खिलाफ नाबाद 24 रन 7 जुलाई 2004 को बनाए थे। अब 22 साल बाद 26 नवंबर 2026 को उनादकट ने यह रिकॉर्ड तोड़ा और नंबर 1 पर काबिज हो गए।